www.tamsasanket.com
वर्षः 29 || अंक 155 || अम्बेडकरनगर
बुधवार
26 अगस्त 2026 || पृष्ठः 08 || मूल्यः ₹2
आज़ादी का अमृत महोत्सव

दैनिक तमसा संकेत

https://epaper.tamsasanket.com
अम्बेडकर नगर व लखनऊ से एक साथ प्रकाशित
डॉ. लोहिया की जन्म भूमि से सर्वप्रथम प्रकाशित समाचार पत्र

मौसम
सूर्योदयः 05:42
सूर्यास्तः 06:34
अधिकतमः 31°00
न्यूनतमः 26°00

पेज 07

विशेष समाचार: विकसित भारत की राह में ... >> पेज 04 | आगरा में टीचर पति को ... >> पेज 06 | ओटीटी रिलीज से पहले विवाद...

3572 युवाओं को मिशन रोजगार के तहत नियुक्ति

3446 प्राविधिक सहायकों (ग्रुप-सी) व 126 मंडी सचिवों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने कृषि विभाग में चयनित सौंपे नियुक्ति पत्र

2017 के पहले खेतों से मोटर चोरी कराते थे सरकार के लोग, अब चोरी की तो अंजाम भुगतना पड़ेगा -सीएम

9 साल में 9.30 लाख से अधिक युवाओं को मिली सरकारी नौकरी

सीएम ने 9 साल में पारदर्शी नियुक्तियों को डबल इंजन सरकार की उपलब्धि बताते हुए कहा कि इस दौरान सरकार ने 9.30 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी उपलब्ध कराई है। किसी भी नियुक्ति पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता। 2017 से पहले तो विज्ञापन निकलते ही चाचा-भतीजे की जोड़ी और महाभारत का खानदान वसूली करने निकल पड़ता था। युवा भटकता था, लेकिन परिणाम नहीं आता था। अंततः माननीय न्यायालय को स्टे करना पड़ता था। नौकरी न पाने वाले युवाओं को लोग किसी काम का नहीं मानते थे, लेकिन गलती युवा की नहीं, बल्कि सरकारी तंत्र में बैठे राजनेताओं, आयोगों व बोर्डों में बैठे बेईमान लोगों की होती थी। >> (शेष पेज 06 पर)

छह महीने में देंगे एक लाख नौकरियां

उत्तर प्रदेश में 9 साल में 9.30 लाख से अधिक युवाओं को मिली सरकारी नौकरीः सीएम योगी

मुहर

मुख्यमंत्री के हाथों नियुक्ति पत्र मिलना उनके लिए खुशी और गर्व का क्षणः चयनित अभ्यर्थी

हेमन्त कृष्ण

तमसा संकेत, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार ने 9 साल में 9.30 लाख से अधिक युवाओं को पारदर्शी ढंग से बिना भेदभाव सरकारी नौकरियां दी हैं। यूपी में कभी एक लाख नौकरियां कल्पना होती थी, लेकिन हम छह महीने के भीतर एक लाख युवाओं को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र देने जा रहे हैं। रिजल्ट की प्रक्रिया चल रही है। मुख्यमंत्री मंगलवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में मिशन रोजगार के तहत उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा कृषि विभाग में नवचयनित 3446 प्राविधिक सहायकों (ग्रुप-सी) व 126 मंडी सचिवों को नियुक्ति पत्र सौंपने के उपरांत युवाओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने नवचयनितों से कहा कि सरकार ने पारदर्शी नियुक्ति दी है तो आप भी इसका लाभ प्रदेश, भावी पीढ़ी और देश को दें। कर्तव्य का ईमानदारी से निर्वहन ही 'नेशन फर्स्ट' की थ्योरी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि 2017 में सीएम बनने के बाद मैंने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अधिकारियों से कहा कि परीक्षा व परिणाम एक महीने में दो। जवाब नकारात्मक मिला तो मैंने कहा कि तुम कुर्सी छोड़ो, मैं एक महीने के अंदर यह कराऊंगा। आज यूपी बोर्ड के 56 लाख अभ्यर्थियों की परीक्षा 14 दिन में होती है और अगले 14 दिन में परिणाम आता है। >> (शेष पेज 06 पर)

60 के ऊपर की उम्रवाली महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा

सीएम ने थपथपाई आयोग की पीठ

सीएम ने कहा कि हमारे आयोग व बोर्ड पारदर्शी नियुक्ति प्रक्रिया से बिना भेदभाव, आरक्षण नियमों का पालन करते हुए योग्य अभ्यर्थियों को मेरिट के अनुसार सफलतापूर्वक नियुक्ति पत्र दिला रहे हैं। यह प्रशंसनीय है। योग्यतम अभ्यर्थियों के चयन से उनकी ऊर्जा का लाभ पूरे प्रदेश को मिलता है।

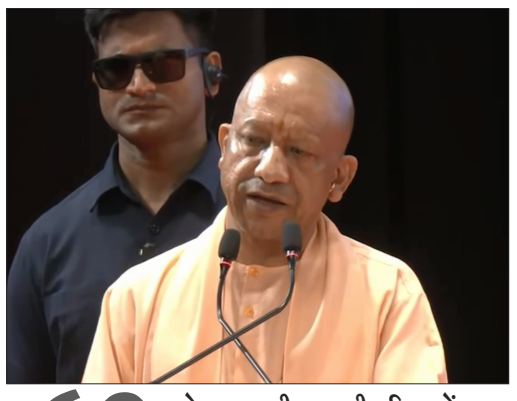

अधियाचन के छह महीने में परिणाम दें

सीएम ने आयोग व बोर्डों के अधिकारियों से कहा कि आपके कार्यों में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। यदि हमने स्वतंत्रता दी है तो समय से परिणाम लाइए। अधियाचन जाने के बाद परिणाम आने में छह महीने से अधिक नहीं लगना चाहिए। एक महीने के अंदर विज्ञापन और अगले दो महीने के अंदर परीक्षा कराएं। प्रक्रिया को सहज-सरल बनाएं, जिससे युवा अपनी ऊर्जा का लाभ दे सके। जब हम युवा ऊर्जा को साथ लेकर चलते हैं तो परिणाम आते हैं।

- 400 करोड़ से इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जाएंगी रक्षाबंधन पर एक करोड़ महिलाओं को यूपी में तोहफा, योगी कैबिनेट की मीटिंग में 24 अहम फैसले

नौजवानों की दुश्मन थी पिछली सरकार

सीएम ने 2017 से पहले यूपी बोर्ड की परीक्षा की दुर्दशा भी बताई और कहा कि तीन महीने परीक्षा और तीन महीने परिणाम आने में लगते थे। फिर अगले तीन महीने त्योहारों के बीच प्रवेश प्रक्रिया चलती थी। बच्चों को पढ़ाई के लिए तीन महीने भी नहीं मिल पाते थे। नौजवानों की दुश्मन सपा सरकार नकल करवाती थी और नौजवानों को किसी लायक नहीं छोड़ती थी।

जम्मू-कश्मीर के शोपियां में 6 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार

हैंड ग्रेनेड और हिजबुल मुजाहिदीन के पोस्टर बरामद

जांच

तमसा संकेत, एजेंसी

श्रीनगर । जम्मू-कश्मीर के शोपियां जिले में सुरक्षाबलों ने सोमवार रात चेकिंग के दौरान 6 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया। उनके पास से 2 हैंड ग्रेनेड और हिजबुल मुजाहिदीन के 5 पोस्टर मिले हैं। वहीं, पुलवामा में भी सुरक्षाबलों ने यरवान जंगल में सर्च ऑपरेशन के दौरान दो संदिग्ध आतंकी सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से एक पिस्तौल, 12 कारतूस और हैंड ग्रेनेड बरामद किए हैं। सुरक्षा एजेंसियां हथियारों के सोर्स और इनके आतंकी नेटवर्क से संबंधों की जांच कर रही हैं। इससे पहले सोपोर के मंजसीर इलाके में सोमवार रात को सुरक्षाबलों ने जॉइंट सर्च ऑपरेशन में हथियार बरामद किए हैं। >> (शेष पेज 06 पर)

- पुलवामा में 2 संदिग्धों को आतंकियों की मदद के आरोप में पकड़ा गया
- सोपोर में सर्च ऑपरेशन के दौरान एके-47, ग्रेनेड और आईइडी बरामद

मिसाइल तकनीक निजी कंपनियों को देने की मंजूरी

आकाश, अस्त्र और नाग मिसाइलें बन सकती हैं

उत्पादन

तमसा संकेत, एजेंसी

नई दिल्ली । रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ की विकसित की गई सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की तकनीक भारतीय निजी कंपनियों को देने की मंजूरी दी है। इन तकनीकों का इस्तेमाल देश में मिसाइलों के उत्पादन के लिए किया जाएगा। इस पहल का मकसद घरेलू रक्षा उत्पादन बढ़ाना है। इसके तहत रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) योग्य रक्षा कंपनियों को मिसाइल तकनीक देगा। रक्षा मंत्रालय ने अभी उन मिसाइलों की कोई सूची जारी नहीं की है, जिन्हें निजी कंपनियां बना सकेंगी। हालांकि, माना जा रहा है कि निजी क्षेत्र को आकाश वायु रक्षा मिसाइल, अस्त्र हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल और नाग टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल बनाने की अनुमति मिल सकती है। >> (शेष पेज 06 पर)

- राजनाथ बोले- घरेलू उत्पादन बढ़ाना टारगेट

फास्ट न्यूज

टीएमसी सांसदों की अयोग्यता पर समयसीमा में फैसला लें स्पीकर

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को TMC के 20 सांसदों की अयोग्यता पर कार्यवाही तय समयसीमा में करने की बात कही। कोर्ट ने साफ किया कि असली मुद्दा नोटिस जारी करने की औपचारिकता नहीं, बल्कि कार्यवाही पूरी करना है। कोर्ट ने 20 बागी सांसदों को नोटिस जारी किया।

विरोध मांग

राहुल-खड़गे की मोदी को चिट्ठी- जाति जनगणना के सवाल बदलें

नई दिल्ली । कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने जाति जनगणना में जातियों के नाम दर्ज करने और डेटा जुटाने के तरीके का विरोध किया है। उन्होंने पीएम मोदी को लेटर लिखकर जनगणना में पूछे जाने वाले सवाल बदलने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इसे बनाने से पहले राजनीतिक दलों, विशेषज्ञों और जनता से सलाह ली जानी चाहिए। जनगणना के सवालों में पिछड़ा वर्ग शब्द नहीं होने पर भी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि इससे देश में ओबीसी आबादी का सही आंकड़ा सामने आने में परेशानी हो सकती है। तेलंगाना और बिहार जैसी प्रक्रिया अपनाने की मांग की है।

रिजिजू बोले- राहुल के निशाने पर सिर्फ हिंदू क्यों

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने सोमवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के पितृसत्ता खत्म करने' बयान पर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि कांग्रेस पार्टी हिंदू परंपराओं को ही निशाना क्यों बनाती है। अल्पसंख्यक महिलाओं की स्थिति पर चुप क्यों रहती है।

युद्ध और राजनीति अलग नहीं

पूर्व सीडीएस अनिल चौहान बोले सरकार को ऑप्शन देना सेना की जिम्मेदारी

चर्चा

- ऑपरेशन सिंदूर विदेशों में भी चर्चा का विषय

तमसा संकेत, एजेंसी

नई दिल्ली। देश के पूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल अनिल चौहान ने कहा कि सेना, राजनीतिक इच्छा का सीधा विस्तार है। किसी देश के राजनीतिक हित सबसे ऊपर होते हैं और सेना उन हितों की रक्षा करने वाले कई माध्यमों में से एक हैं।

पूर्व CDS ने कहा- "शुरुआत इस बात से करते हैं कि राजनीति और युद्ध अलग नहीं हैं। क्लॉजविट्ज ने कहा था कि युद्ध दूसरे माध्यमों से राजनीति को आगे बढ़ाना है।"

पूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल अनिल चौहान ने मंगलवार को नई दिल्ली में ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद के हालात पर चर्चा की।

यह आयोजन विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन ने रखा था। इस दौरान पूर्व CDS ने राष्ट्रीय सुरक्षा और लोकतांत्रिक शासन के रिश्ते पर बात की। >> (शेष पेज 06 पर)

चौहान बोले- युद्ध और राजनीति अलग नहीं

जनरल चौहान ने प्रूशियाई जनरल कार्ल वॉन क्लॉजविट्ज की बात जिक्र किया कि युद्ध दूसरे माध्यमों से राजनीति को आगे बढ़ाने का तरीका है। प्रूशियाई जनरल कार्ल वॉन क्लॉजविट्ज की किताब 'ऑन वॉर' (वॉम क्रिगे) आधुनिक पश्चिमी सैन्य सिद्धांत की आधारशिला मानी जाती है। यह किताब उनकी मौत के बाद 1832 में उनकी पत्नी मैरी वॉन ब्रुहल ने प्रकाशित की थी। क्लॉजविट्ज ने नेपोलियन के खिलाफ अभियान में हिस्सा लिया था।

इलाहाबाद हाईकोर्ट बोला सेक्युलरिज्म के लिए यूनिफॉर्म जरूरी, नाबालिग छात्रा की याचिका खारिज

स्कूल में हिजाब पहनने की इजाजत नहीं : हाईकोर्ट

इनकार

तमसा संकेत, एजेंसी

प्रयागराज । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्कूलों में हिजाब पहनने की इजाजत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने सोमवार को कहा स्कूल में यूनिफॉर्म के नियम का पालन करना जरूरी है। इससे बच्चों में बराबरी की भावना रहती है। स्कूल की अपनी पहचान भी बनती है।

हाईकोर्ट ने कहा, यूनिफॉर्म की बदौलत बिना किसी धार्मिक भेदभाव वाला माहौल बना रहता है। इसलिए कोई भी छात्र या छात्रा स्कूल के तय किए गए ड्रेस कोड को बदलने की जिद नहीं कर सकती। कोर्ट ने कहा-स्कूल में व्यक्तिगत आधार पर हिजाब पहनने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। यह यूनिफॉर्म के विचार के खिलाफ होगा। >> (शेष 06 पर)

> हिजाब विवाद पर 13 अक्टूबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच का फैसला एकमत नहीं था। दोनों जजों की राय अलग रही।

स्कूलों में हिजाब विवाद कर्नाटक से शुरू हुआ

कर्नाटक में हिजाब विवाद जनवरी 2022 में उडुपी के एक सरकारी कॉलेज से शुरू हुआ। कुछ मुस्लिम छात्राओं ने हिजाब पहनकर कक्षा में बैठने की मांग की, जबकि कॉलेज प्रशासन ने इसे यूनिफॉर्म नियम के खिलाफ बताया। इसके बाद विरोध दूसरे कॉलेजों तक पहुंचा और कुछ जगह भगवा शॉल पहनकर जवाबी प्रदर्शन हुए।

15 मार्च 2022 को कर्नाटक हाईकोर्ट ने छात्राओं की याचिका खारिज करते हुए कहा कि हिजाब इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है और स्कूल के तय ड्रेस कोड का पालन कराया जा सकता है।

श्रद्धांजलि : बीपी मंडल की जयंती पर अखिलेश यादव ने भाजपा पर साधा निशाना

2027 का चुनाव लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण : अखिलेश

- 2027 का विधानसभा चुनाव लोकतंत्र के लिए अहम
- बोले- जनता भाजपा की चाल समझ चुकी है

तमसा संकेत, एजेंसी

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के प्रदेश मुख्यालय, विक्रमादित्य मार्ग लखनऊ समेत प्रदेश के सभी जनपदों में मंगलवार को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं सामाजिक न्याय के पुरोधा बीपी मंडल की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बीपी मंडल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने पिछड़े और वंचित वर्गों के उत्थान तथा सामाजिक न्याय के लिए मंडल के योगदान को याद किया।

कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि 2027 का विधानसभा चुनाव लोकतंत्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। >> (शेष पेज 06 पर)

कानून व्यवस्था पर भी उठाए सवाल

सपा प्रमुख ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर भी भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अपराध लगातार बढ़ रहे हैं और अपराधियों को सत्ता का संरक्षण मिल रहा है। वहीं, निर्दोष लोगों को परेशान किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि अन्याय और अत्याचार चरम पर है तथा लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है।

महंगाई को लेकर सरकार पर हमला

अखिलेश यादव ने कहा कि त्योहारों का समय आने वाला है, लेकिन चीनी, तेल समेत रोजमर्रा की खाद्य वस्तुओं के दाम बढ़ गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कालाबाजारी और मुनाफाखोरी के जरिए गरीब और मध्यम वर्ग की जेब पर बोझ बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने बढ़ती महंगाई के लिए भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहराया।

> सपा अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी बढ़ी है तथा भाजपा के करीबी उद्योगपति मुनाफा कमा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुनाफाखोरी के कारण महंगाई लगातार बढ़ रही है और आम जनता पर इसका सीधा असर पड़ रहा है।

नई पीढ़ी को जिम्मेदारी देने का समय : गडकरी

अब पहले जितना काम नहीं कर सकता

स्पीच

तमसा संकेत, एजेंसी

नागपुर । केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के 'जिम्मेदारी नई पीढ़ी के हाथों में सौंपने' वाले बयान पर मंगलवार को सफाई आई। गडकरी के ऑफिस ने कहा, 'उन्होंने अपने लक्ष्मणराव मानकर ट्रस्ट से जुड़े सामाजिक कार्यों की जिम्मेदारी नई पीढ़ी को सौंपने की बात कही थी।'

ऑफिस ने कहा कि उनके बयान का राजनीति से कोई संबंध नहीं है। दरअसल, कई मीडिया रिपोर्ट्स में गडकरी के इस बयान को उनके राजनीति से रिटायरमेंट लेने से जोड़ दिया गया था। गडकरी का यह बयान 23 अगस्त का है। उन्होंने पुणे के काटोल में कहा था, 'अब ज्यादा काम नहीं कर सकता। जब कर सकता था, तब किया। नई पीढ़ी को जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए।'

नितिन 37 साल से ज्यादा राजनीति में हैं। पिछले 12 साल से मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। >> (शेष पेज 06 पर)

- 2 मौके जब गडकरी पब्लिक इवेंट में बेहोश हुए

बारिश के बाद डेढ़ घंटे में पानी साफ करने का दावा, महापौर-नगर आयुक्त शहर का हाल जानने निकले

नगर निगम के दावों की खुली पोल, रुद्राक्ष पर जलजमाव

जलजमाव

तमसा संकेत, एजेंसी

वाराणसी । वाराणसी में सोमवार देर रात से शुरू हुई बारिश मंगलवार सुबह तक होती रही। इस बारिश के बाद वाराणसी के ज्यादातर हिस्सों में वाटर लॉगिंग का नजारा देखने को मिला। लंका, बीएलडब्ल्यू, रविन्द्रपुरी, कबीरनगर कालोनी, दुर्गाकुंड, अस्सी चौराहा, भेलूपुर, रेवड़ी तालाब, रामापुरा, नई सड़क, बेनियाबाग, पीलीकोठी, आजाद पार्क, औसानगंज चौराहा, डिगिया, बजरडीहा, नवाबगंज, खजुरी, कचहरी, पिपलानी कटरा, गोदौलिया, कैंटोनमेंट एरिया, सिगरा, महमूरगंज,

नगर निगम ने डेढ़ घंटे में पानी साफ करने का किया दावा। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर के गेट पर लगा रहा पानी।

बनारस स्टेशन मार्ग, इन स्थानों पर जलभराव देखने को मिला। जिसपर नगर निगम ने पानी रुकने के बाद कई टीमें फिल्ड में उतरी जिसमें नगर आयुक्त और महापौर भी शामिल रहे। सफाई शुरू की गयी और दावा किया की डेढ़ घंटे में पूरे शहर का पानी निकाल दिया गया। लेकिन साफ-सफाई के इस दावे की पोल दोपहर तीन बजे के बाद तक

रुद्राक्ष के गेट पर लगा रहा पानी

नगर निगम के दावों के बीच दोपहर 3 बजे निगम कार्यालय के बगल में स्थित रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर के मेन गेट पर पानी लगा रहा। यह नगर निगम के उन दावों की पोल खोल रहा था। जिसमें डेढ़ घंटे में पानी निकालने की बात कही गयी थी। फिलहाल मौके पर को कर्मचारी या अधिकारी इस पानी की निकासी के लिए नहीं दिखाई दिया जबकि ड्रेनज गेट पर ही बना है उसमें से भी पानी पास होता नहीं दिखा।

नगर निगम के प्रधान कार्यालय से

निरीक्षण के बाद नगर आयुक्त ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि फोन या अन्य माध्यम से प्राप्त जलभराव की शिकायतों का तत्काल निस्तारण किया जाए। अधिकारी स्वयं मौके पर पहुंचकर समस्या के मूल कारण का चिन्हांकन करें और त्वरित जल-निकासी सुनिश्चित कराएं। नगर निगम की टीमें सभी संवेदनशील बिंदुओं पर लगातार निगरानी रख रही हैं।

सटे रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का मुख्य द्वार ने खोल दी। जहां जलभराव था। इस दौरान नगर निगम ने शहर में रातभर हुई मूसलाधार

वाराणसी के बीएचयू स्थित सिंहद्वार पर जलजमाव का दृश्य।

वाराणसी में जलभराव से दिक्कतें ही दिक्कत

वाराणसी में भारी जलजमाव की गंभीरता को देखते हुए महापौर अशोक कुमार तिवारी ने जलकल विभाग के अधिकारियों संग खुद मोर्चे पर कमान संभाली। उन्होंने रविंद्रपुरी समेत विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों का जायजा लिया और अपनी मौजूदगी में जल-निकासी का काम पूरा कराया। इस दौरान जलकल विभाग के महाप्रबंधक अनूप सिंह और अधिशासी अभियंता आगम कटियार समेत तमाम आला अधिकारी मौके पर डटे रहे। निगम का दावा है की इससे डेढ़ घंटे से भी कम में सड़कों पर से पानी साफ़ हो गया।

बारिश और तेज हवाओं शहर के 11 प्रमुख मार्गों पर गिरे पेड़ों को भी हटवाया। जिससे आवागमन बाधित हुआ। निगम की टीमों ने तत्परता दिखाते हुए सुंदरपुर, सुसवाही, संसदीय कार्यालय के पास, आदमपुर पुलिस चौकी के पास, आदमपुर वार्ड, लक्ष्मी मंदिर (अशोक विहार कॉलोनी) में दो स्थानों पर तथा आशापुर से हवेलियां चौराहा तक तीन स्थानों पर गिरे पेड़ों की कटाई कराकर रास्ते तुरंत क्लियर कराए।

मिलावटखोरों पर शिकंजा रक्षाबंधन से पहले 3416 किलो नमकीन जब्त

तमसा संकेत, एजेंसी

बाराबंकी। में रक्षाबंधन पर्व से पहले खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। इसी क्रम में बाराबंकी और अयोध्या की संयुक्त टीम ने अहमदपुर टोल प्लाजा पर खाद्य पदार्थों से लदे 22 वाहनों की जांच की। कार्रवाई के दौरान खोया, पनीर और नमकीन के चार नमूने लिए गए। प्रथम दृष्टया मानकों के विपरीत पाए जाने की आशंका पर टीम ने 3,416 किलोग्राम नमकीन जब्त की, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 3 लाख 21 हजार रुपये है।

अभियान के तहत नवाबगंज तहसील के कोडरी गांव में खोया निर्माण इकाइयों का सघन निरीक्षण किया गया। टीम ने चार निर्माण इकाइयों से खोया के चार नमूने जांच के लिए लिए। इसके अलावा देवा क्षेत्र में पनीर और खोया निर्माण इकाइयों की जांच की गई। यहां संचालकों को खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और स्वच्छता के मानकों

का पालन करने के निर्देश दिए गए।

बाराबंकी नगर के छाया चौराहे के आसपास सचल खाद्य प्रयोगशाला के जरिए 18 खाद्य पदार्थों की मौके पर जांच की गई। इस दौरान लोगों को खाद्य पदार्थों में मिलावट के प्रति जागरूक भी किया गया। वहीं, पटेल चौराहा स्थित मिठाई की दुकानों की जांच के दौरान राधिका स्वीट्स से समोसे का एक नमूना भी लिया गया। खाद्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार, मिलावट के खिलाफ यह अभियान रक्षाबंधन तक लगातार जारी रहेगा। खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता या निर्माण प्रक्रिया मानकों के विपरीत पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठानों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।

फास्ट न्यूज

माफिया अतीक के कब्जे वाली जमीन पर पीडीए बनाएगा फ्लैट

प्रयागराज । प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के गढ़ रहे चकिया और कसारी-मसारी क्षेत्र में अब एक नई आवासीय परियोजना शुरू होने जा रही है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण (PDA) की प्रस्तावित पद्म आवास योजना को रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) से मंजूरी मिल गई है। इस मंजूरी के बाद परियोजना के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है।

बीएचयू का अस्पताल 15 घंटे की बारिश में जलमग्न

वाराणसी । वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) के सर सुंदरलाल अस्पताल की व्यवस्थाएं मंगलवार को लगातार बारिश के बाद बेबस नजर आईं। पिछले 15 घंटे की बारिश से अस्पताल में पूरा इलाका जलमग्न हो गया।अस्पताल परिसर में जलभराव ने मरीजों और तीमारदारों की मुश्किलें कई गुना बढ़ा दीं। अस्पताल के ओपीडी क्षेत्र से लेकर जांच काउंटर तक जाने वाले रास्ते कमर तक पानी में डूबे रहे। ऐसे में बड़ी संख्या में मरीज अस्पताल पहुंचने के बावजूद इलाज और जांच कराए बिना वापस लौटने को मजबूर हुए।

जलभराव मुद्दे पर गरजे कांग्रेसी

प्रयागराज। प्रयागराज में बारिश के बाद पूरे शहर में जलभराव को लेकर राजनीति गर्म है। एक बार फिर मंगलवार को कांग्रेसियों ने इस मुद्दे पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने नगर निगम कार्यालय पहुंच नारेबाजी की। प्रदेश महासचिव मुकुंद तिवारी के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नगर विकास मंत्री के इस्तीफे की मांग की।

17 सितंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव

तमसा संकेत, एजेंसी

प्रयागराज । इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन (HCBA) के सत्र 2026-2027 के वार्षिक चुनाव का विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। मतदान 17 सितंबर को सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक क्रिकेट ग्राउंड में कराया जाएगा। चुनाव प्रक्रिया मुख्य चुनाव अधिकारी वरिष्ठ अधिवक्ता एस.एफ.ए. नकवी और चुनाव अधिकारियों वशिष्ठ तिवारी, जे.बी. सिंह, राज कुमार शुक्ला, लक्ष्मी कांत मिश्रा और अनुभव शुक्ला की निगरानी में संपन्न होगी।

चुनाव के लिए 25 अगस्त को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित कर दी गई है। सूची के मुताबिक कुल मतदाताओं में 10,609 पुरुष अधिवक्ता, 742 महिला अधिवक्ता और 134 सीनियर अधिवक्ता शामिल हैं।

इस बार चुनाव की खास बात यह है कि बार एसोसिएशन के चुनावी

पहली बार महिलाओं को आरक्षण, 11,485 अधिवक्ता डालेंगे वोट

इतिहास में पहली बार महिला अधिवक्ताओं के लिए अलग सीटें आरक्षित की गई हैं। उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, संयुक्त सचिव और गवर्निंग काउंसिल के पदों में महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है। 26 अगस्त से नामांकन प्रक्रिया जारी कार्यक्रम के अनुसार 26 से 28 अगस्त तक सुबह 10 बजे से शाम चार बजे तक नामांकन पत्रों की बिक्री और जमानत राशि जमा की जाएगी। 29 अगस्त से 1 सितंबर तक सुबह 10 बजे से शाम चार बजे तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे।

172 प्रतिभागियों ने कराया पंजीकरण, विशेषज्ञों ने आधुनिक जियोस्पेशियल तकनीकों की दी जानकारी

जीआईएस और रिमोट सेंसिंग पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित

तमसा संकेत, संवाददाता

बरेली। बरेली कॉलेज के पर्यावरण विज्ञान विभाग की ओर से "Navigating the Future: GIS & Remote Sensing" विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का सफल आयोजन किया गया। कार्यशाला का आयोजन प्रबंधन समिति के सचिव देवमूर्ति के संरक्षण, प्राचार्य प्रो. ओपी राय के निर्देशन और कार्यवाहक प्राचार्य प्रो. वंदना शर्मा के नेतृत्व में हुआ। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों एवं शोधार्थियों को जीआईएस और रिमोट सेंसिंग की आधुनिक तकनीकों, उनके व्यावहारिक उपयोग तथा शोध और व्यावसायिक क्षेत्र में संभावनाओं से परिचित कराना रहा।

कार्यक्रम की शुरुआत पर्यावरण

विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष प्रो. जसपाल सिंह के वेलकम एड्रेस से हुई। उन्होंने कार्यशाला के उद्देश्य एवं उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए अतिथियों, रिसोर्स पर्सन्स और प्रतिभागियों का स्वागत किया।

इसके बाद बरेली कॉलेज की उप-प्राचार्य प्रो. वंदना शर्मा ने इनॉग्रल रिमार्क्स प्रस्तुत किए।

पूर्व छात्रा ने दिया तकनीकी व्याख्यान और प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशन

कार्यशाला में पर्यावरण विज्ञान विभाग की पूर्व छात्रा एवं जीआईएस तथा रिमोट सेंसिंग ट्रेनर श्रीमती श्रुति सक्सेना ने ऑफलाइन माध्यम से तकनीकी व्याख्यान एवं प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशन दिया। उन्होंने ArcGIS, QGIS, Google Earth Pro, Remote Sensing, LULC Mapping, Spatial Analysis और Environmental Assessment से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी साझा की।

उन्होंने विद्यार्थियों एवं शोधार्थियों को जीआईएस और रिमोट सेंसिंग जैसी आधुनिक तकनीकों के महत्व को समझने तथा इनके व्यावहारिक प्रयोगों

पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में बढ़ रहा उपयोग

प्रो. वंदना शर्मा ने कहा कि वर्तमान समय में जियोस्पेशियल तकनीकों का उपयोग पर्यावरण अध्ययन, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, जलवायु अध्ययन और विभिन्न शोध क्षेत्रों में तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने प्रतिभागियों से विशेषज्ञों द्वारा साझा की गई जानकारी का अधिकतम लाभ उठाने और इसे अपने अकादमिक एवं व्यावसायिक विकास में उपयोग करने का आह्वान किया। कार्यशाला को लेकर प्रतिभागियों में विशेष उत्साह देखने को मिला। इसमें ऑनलाइन माध्यम से कुल 172 प्रतिभागियों ने पंजीकरण कराया, जिनमें विभिन्न महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी, शोधार्थी और शिक्षक शामिल रहे।

को अकादमिक और शोध कार्य से जोड़ने के लिए प्रेरित किया।

K. Banerjee Centre of Atmospheric and Ocean Studies, University of Allahabad के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. सुधीर कुमार सिंह ने ऑनलाइन माध्यम से तकनीकी सत्र लिया। उन्होंने रिमोट सेंसिंग, जियोइन्फॉर्मेटिक्स, क्लाइमेट चेंज, एनवायरनमेंटल मॉडलिंग और हाइड्रोलॉजिकल मॉडलिंग से जुड़े विषयों पर जानकारी दी।

कहा- 120 लीटर गन्ने का जूस बेच रही है, जेवर से बीएसपी कैंडिडेट का किया ऐलान

कांग्रेस ने छात्रों के आंदोलन को हाईजैक किया : आकाश आनंद

तमसा संकेत, एजेंसी

नोएडा। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के नेशनल कोआर्डिनेटर आकाश आनंद आज (मंगलवार) जेवर में जनसभा को संबोधित किया। दनकौर के आदर्श इंटर कॉलेज में आयोजित जनसभा में करीब 20 हजार समर्थक पहुंचे। इस सम्मेलन में जेवर विधानसभा सीट से बसपा प्रत्याशी के नाम की घोषणा होने की संभावना है। पार्टी के इस बड़े कार्यक्रम को 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है। खास बात यह है कि अपने गृहजनपद गौतमबुद्ध नगर में आकाश आनंद का यह पहला बड़ा राजनीतिक कार्यक्रम है।

आकाश आनंद का अपने गृहज-नपद गौतमबुद्ध नगर में यह पहला

बड़ा राजनीतिक कार्यक्रम है। इसलिए बसपा के लिए इस सम्मेलन की अहमियत और बढ़ गई है। पार्टी इसे केवल कार्यकर्ता सम्मेलन तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि इसके जरिए 2027 विधानसभा चुनाव के लिए अपना राजनीतिक आधार मजबूत करने की तैयारी में है। सम्मेलन में जेवर विधानसभा सीट से प्रत्याशी के नाम का ऐलान होने की चर्चा है। सतवीर नागर पूर्व में गौतमबुद्ध नगर लोकसभा सीट से भी चुनाव लड़ चुके हैं। अगर पार्टी

एक्सप्रेसवे को लेकर सरकार पर हमला

आकाश आनंद ने कहा कि भाजपा नेताओं ने दावा किया था कि 2024 तक भारत की सड़कें अमेरिका की सड़कों से बेहतर होंगी, लेकिन जमीनी हकीकत अलग है। उन्होंने लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे का उदाहरण देते हुए कहा कि करीब 4,500 करोड़ रुपये की लागत से बने इस एक्सप्रेसवे में शुरू होने के 18 दिन के अंदर 80 से ज्यादा जगहों पर सड़क धंस गई।

सतवीर नागर के नाम पर मुहर लगाती है तो जेवर में गुर्जर समाज को साधने की रणनीति साफ दिखाई देगी। स्थानीय चेहरे को आगे कर बसपा गुर्जर मतदाताओं के साथ ही

महंगाई पर भाजपा को घेरा

आकाश आनंद ने भाजपा के पुराने चुनावी नारे 'बहुत हुई महंगाई की मार, अबकी बार भाजपा सरकार' का जिक्र करते हुए महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि 2014 में गैस सिलेंडर करीब 400 रुपये का था, जो अब करीब 1200 रुपये में मिल रहा है। इसी तरह पेट्रोल की कीमत 60 रुपये के आसपास थी, जो अब 110 रुपये तक पहुंच गई है। उन्होंने डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत का भी जिक्र किया। कहा कि 2014 में एक डॉलर करीब 60 रुपये का था, जो अब 100 रुपये के आसपास पहुंच गया है।

युवाओं और क्षेत्र के अन्य सामाजिक समूहों के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर सकती है। आकाश आनंद ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों के आंदोलन का जिक्र करते हुए कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों पर आंदोलन को हाईजैक करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि छात्रों के कंधे पर बंदूक रखकर अपनी राजनीति चमकाने का काम किया गया।

चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के बिशप समेत पांच पर एफआईआर

तमसा संकेत, एजेंसी

प्रयागराज । सेंट एंड्रयूज डिग्री कॉलेज गोरखपुर के कार्यवाहक प्राचार्य प्रो. एस. डोमिनिक राजकुमार की शिकायत पर चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया (CNI) के पदाधिकारियों समेत पांच लोगों के खिलाफ कैंट थाने में FIR दर्ज हुई है। इनमें CNI की लखनऊ डायसिस के बिशप मॉरिस एडगर दान का नाम भी शामिल है। आरोप है कि हाईकोर्ट में विवाद विचाराधीन होने के बावजूद फर्जी नियुक्ति पत्र और सर्कुलर तैयार कर कॉलेज में कार्यवाहक प्राचार्य नियुक्त करने की कोशिश की गई। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है।

प्रोफेसर एस. डोमिनिक राजकुमार ने बताया कि कॉलेज का संचालन सेंट एंड्रयूज कॉलेज एसोसिएशन नामक सोसायटी के माध्यम से होता है। वादी का कहना है कि सोसायटी की पंजीकृत नियमावली में प्रबंध समिति को

प्रयागराज में सेंट एंड्रयूज डिग्री कॉलेज में फर्जी नियुक्ति का प्रयास करने पर कार्रवाई

कॉलेज के प्राचार्य की नियुक्ति, निलंबन और बर्खास्तगी का अधिकार दिया गया है। शिकायत में कहा गया है कि सोसायटी की प्रबंध समिति को लेकर विवाद हाईकोर्ट में विचाराधीन है। इसी बीच सहायक रजिस्ट्रार, फर्म्स, सोसायटीज एवं चिट्स, गोरखपुर मंडल ने 7 मार्च 2026 को पत्र जारी कर निर्देश दिया था कि हाईकोर्ट के निर्णय के बिना प्रबंध समिति की बैठक कर कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता।

छापा : अब पेनाल्टी की बारी, कोल्ड स्टोरेज में पड़ा था छापा, व्यापारियों पर जुर्माना तय करने में जुटा विभाग

30 करोड़ का माल सीज

तमसा संकेत, एजेंसी

गोरखपुर । पिपराइच क्षेत्र में स्थित पूर्व मंत्री एवं भाजपा नेता जितेंद्र जायसवाल उर्फ पप्पू भैया के कोल्डस्टोरेज में जीएसटी विभाग का छापा पड़ने के बाद लगभग 30 करोड़ रुपये का माल सीज किया गया है। विभाग के पास उन व्यापारियों की सूची है, जिनके माल यहां रखे गए थे।

टैक्स चोरी की गणना की जा रही है और यह भी तय किया जा रहा है कि किसपर कितनी पेनाल्टी लगानी है। एक फर्म ने पेनाल्टी व टैक्स के रूप में लगभग 11 लाख रुपये रविवार को जमा कराए हैं। अभी और भी व्यापारियों को पेनाल्टी जमा करनी होगी। पेनाल्टी व टैक्स के रूप में विभाग को करोड़ों रुपये मिलने का अनुमान है।

5 अगस्त को इस कोल्ड स्टोरेज में छापा मारा गया था। यहां बड़े पैमाने पर मूंगफली, मिर्च एवं अन्य मसाले मिले थे। जांच के दौरान टैक्स में गड़बड़ी का माला प्रकाश में आया। जिसके बाद वहां माल रखने वाली लगभग 70 फर्मों को नोटिस जारी किया गया।

15 दिन में यानी 22 अगस्त तक जवाब देना था लेकिन बामुश्किल 2 से 3 फर्मों ने ही जवाब दाखिल किया है। एक फर्म ने तो लगभग 11 लाख रुपये का जुर्माना जमा करा दिया है। अब विभाग हय तय करने में जुटा है कि किस फर्म पर कितना जुर्माना लगाया जाएगा। जिनके पास कागज नहीं है, उन्हें अधिक पेनाल्टी व टैक्स

मूंगफली में टैक्स चोरी का शक भाजपा महानगर उपाध्यक्ष मनीष जैन की फर्म सिद्धि विनायक ट्रेडर्स पर भी है। इस फर्म को भी नोटिस जारी किया गया है। भाजपा नेता की फर्म होने के कारण राजनीतिक हलकों में भी काफी चर्चा है। इस मामले में नाम आने के बाद पार्टी के अंदर भी चर्चा शुरू हो गई है।

देना होगा। जिन फर्मों के पास कागज होगा, उन्हें कुछ कम पेनाल्टी देनी होगी।

यह भी देखा जा रहा है कि नोटिस का जवाब कितने लोगों ने नहीं दिया है। उसके बाद रिमाइंडर नोटिस भेजा जाएगा।

मूंगफली में ज्यादा खेल

कोल्ड स्टोरेज पर छापे के दौरान वहां मिले खाली ट्रक से पोल खुल गई। ट्रक संचालक के पास बिहार का ई वे बिल था। विभगा ने जब चेक किया तो ट्रक कभी बिहार गया ही नहीं था। शाहजहांपुर से उसपर मूंगफली आयी थी, इसलिए बरेली के ज्वाइंट कमिश्नर को इसकी जानकारी दी गई।

बरेली और गोरखपुर जोन की संयुक्त कार्रवाई में यह निकलकर आया कि कई फर्मों को शाहजहांपुर से माल भेजा गया है। बाद में उन फर्मों को भी नोटिस जारी किया गया।

मूंगफली की खरीद-बिक्री में फर्जी बिलों के जरिए करोड़ों रुपये का कारोबार दिखाकर जीएसटी चोरी की आशंका विभाग को है। गोरखपुर के विश्वनाथ कोल्डस्टोरेज पर छापा पड़ने के बाद यह खेल पकड़ में आया था। दरअसल शाहजहांपुर से बंगाल व बिहार के लिए बिलिंग होती थी लेकिन माल गोरखपुर में ही खाली कर लिया जाता था।

सतीश महाना ने जनप्रतिनिधियों से संयम और सतर्कता का किया आह्वान

तमसा संकेत, संवाददाता

अपयश के बाद भी जनता की सेवा में जुटे रहने वाला जनप्रतिनिधि ही सबसे बड़ा जनप्रतिनिधि : सतीश महाना

लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा के माननीय अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि समाज सेवा का अवसर बड़े सौभाग्य से मिलता है। अपयश के बाद भी जनता की सेवा में निरंतर जुटे रहने वाला जनप्रतिनिधि ही वास्तव में सबसे बड़ा जनप्रतिनिधि होता है। महाना ने कहा कि सामान्य नागरिक के लिए उसका जनप्रति-निधि ही सबसे बड़ा सहारा होता है।

लखनऊ के होटल सेंट्रम में आज "साइबर सुरक्षा : ए डिजिटल सिक्योरिटी ब्रीफिंग फॉर लेजिस्लेटर्स" विषयक चौथी एवं अंतिम कार्यशाला का आयोजन किया गया।

महाना ने कहा कि एक जनप्रति-निधि समाज के लिए पूरे दिन मेहनत करता है लेकिन सोशल मीडिया पर दो -चार नेगेटिव कमेंट्स से वो हताश हो जाता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि ऐसे

नकारात्मक कमेंट्स से हताश होने की आवश्यकता नहीं है। आप जनता की सेवा करते रहिए। आपकी सेवा का मूल्यांकन जनता को करना होता है। मा अध्यक्ष श्री सतीश महाना ने कहा कि जनप्रतिनिधि का दायित्व केवल चुनाव तक सीमित नहीं होता, बल्कि जनता के सुख-दुःख में उसके साथ खड़ा रहना और क्षेत्र के विकास के लिए निरंतर प्रयास करना भी उसकी जिम्मेदारी है। जनसेवा के इस दायित्व को पूरी निष्ठा, संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ निभाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि राजनीतिक क्षेत्र बेहद चुनौतीपूर्ण है और पिछले चार वर्षों में विधानसभा के सभी सदस्यों ने अपने-अपने क्षेत्रों में पूरी निष्ठा से कार्य किया है। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि विधानसभा चुनाव निकट हैं, ऐसे में सभी सदस्यों को संयम और मर्यादा के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करना होगा। राजनीतिक जीवन में परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि का जनता के प्रति दायित्व सदैव बना रहता है। इसलिए सभी सदस्यों को लोकतांत्रिक मूल्यों, संसदीय मर्यादाओं और जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कार्य करना चाहिए।

महामाया मेडिकल कॉलेज में पखवाड़े का आगाज, 25 अगस्त से 8 सितंबर तक चलेगा जागरूकता अभियान

नेत्रदान से मिलेगी नई रोशनी

अभियान

बृजेंद्र वीर सिंह

तमसा संकेत, अंबेडकरनगर। महामाया राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज में मंगलवार को 41वें राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़े का शुभारंभ हुआ। इस दौरान नेत्रदान को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए यात्रा निकाली गई। अभियान में नेत्रदान से जुड़ी भ्रांतियां दूर करने और लोगों को वैज्ञानिक जानकारी देने पर जोर दिया गया। नेत्र विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. अमित कुमार पटेल के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानाचार्य डॉ. मुकेश यादव ने प्रशासनिक भवन से जागरूकता यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यात्रा अकादमिक भवन तक गई। इसमें मेडिकल कॉलेज के चिकित्सक, नर्सिंग स्टाफ और छात्र-छात्राओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में उप प्रधानाचार्य डॉ. उमेश वर्मा, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. बृजेश कुमार, चीफ प्रॉक्टर डॉ. प्रमोद यादव सहित विभिन्न विभागों के चिकित्सक मौजूद रहे। नर्सिंग फैकल्टी, एमबीबीएस और नर्सिंग के छात्र-छात्राओं ने भी जागरूकता यात्रा में भाग लिया। नेत्र विभाग के डॉ. साजन देव केसर, डॉ. सृष्टि नागराजन, डॉ. दीपक और डॉ. वर्षा के साथ पीजी रेजिडेंट्स, सीनियर रेजिडेंट्स, इंटर्न्स और नर्सिंग स्टाफ ने अभियान में सहभागिता की। मेडिकल कॉलेज की ओर से बताया गया कि 25 अगस्त से 8 सितंबर तक नेत्रदान जागरूकता से जुड़े कार्यक्रम चलाए जाएंगे। अभियान का मुख्य उद्देश्य नेत्रदान को लेकर मौजूद भ्रांतियों को दूर करना और लोगों को इसके बारे में सही एवं वैज्ञानिक जानकारी उपलब्ध कराना है।

कौन कर सकता है नेत्रदान, कब होता है दान

पखवाड़े के दौरान नेत्रदान से जुड़े कई सवालों के जवाब दिए जाएंगे। इसमें कौन नेत्रदान कर सकता है, नेत्रदान कब किया जाता है, इससे शरीर पर कोई असर पड़ता है या नहीं और क्या हर उम्र का व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है, जैसे विषय शामिल हैं।

12 से 13 लाख लोग कॉर्नियल ब्लाइंडनेस से प्रभावित

कार्यक्रम में बताया गया कि देश में करीब 12 से 13 लाख लोग कॉर्नियल ब्लाइंडनेस से प्रभावित हैं। हर साल लगभग 70 हजार नेत्रदान प्राप्त होते हैं। इसके मुकाबले देश में कम से कम एक लाख कॉर्निया डोनेशन तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है।

प्राप्त होने वाले सभी कॉर्निया प्रत्यारोपण के लिए उपयुक्त नहीं होते। विभिन्न कारणों से करीब आधे कॉर्निया ही प्रत्यारोपण के लिए स्वीकार्य हो पाते हैं। इसलिए अभियान के दौरान अधिक से अधिक लोगों तक सही जानकारी पहुंचाने पर जोर दिया जाएगा।

कार्यक्रम की शुरुआत प्रशासनिक भवन परिसर में लगाए गए नेत्रदान संकल्प पोस्टर से हुई। चिकित्सकों, कर्मचारियों और विद्यार्थियों ने पोस्टर पर नेत्रदान को लेकर अपना संकल्प दर्ज किया। इसके बाद जागरूकता यात्रा के माध्यम से नेत्रदान का संदेश लोगों तक पहुंचाया गया।

अशरफपुर किछौछा नगर पंचायत की कमान अब एसडीएम के हाथ

अध्यक्ष ओमकार गुप्ता के पदच्युत होने के बाद डीएम ने टांडा एसडीएम संजीव कुमार को बनाया प्रशासक

तमसा संकेत, संवाददाता

अंबेडकरनगर। अशरफपुर किछौछा नगर पंचायत के अध्यक्ष ओमकार गुप्ता को पद से हटाए जाने के बाद नगर पंचायत की प्रशासनिक जिम्मेदारी अब टांडा के उपजिलाधिकारी संजीव कुमार संभालेंगे। जिलाधिकारी ईशा प्रिया ने उन्हें नगर पंचायत का प्रशासक नियुक्त किया है। शासन के नगर विकास अनुभाग-1 की ओर से 22 अगस्त को ओमकार गुप्ता को अध्यक्ष पद से पदच्युत किए जाने का आदेश जारी किया गया था। आदेश में उनके खिलाफ प्रतिकूल तथ्य पाए जाने का उल्लेख किया गया है। अध्यक्ष पद रिक्त होने के बाद नगर पंचायत के कामकाज को सुचारु रखने के लिए प्रशासक की नियुक्ति की गई है।

जिलाधिकारी ईशा प्रिया के अनुसार, राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से अध्यक्ष पद के उपचुनाव की प्रक्रिया पूरी होने तक एसडीएम टांडा संजीव कुमार नगर पंचायत अध्यक्ष की शक्तियों, कृत्यों और दायित्वों का निर्वहन करेंगे।

इस दौरान नगर पंचायत के प्रशासनिक और विकास कार्य प्रशासक की देखरेख में संचालित होंगे। ओमकार गुप्ता के कार्यकाल को लेकर पूर्व में भी शिकायतें और जांच हुई थीं। नगर पंचायत से जुड़े विभिन्न मामलों की शिकायतें शासन स्तर तक पहुंची थीं।

वर्ष 2025 में सफाई, पेयजल और प्रकाश व्यवस्था से जुड़े कर्मचारियों को काम से विरत रहने का निर्देश देने और हड़ताल अवधि का पूरा वेतन दिलाने के लिए अधिशासी अधिकारी पर दबाव बनाने के आरोप लगाए गए थे। इसके अलावा होली और रमजान के दौरान कर्मचारियों के वेतन भुगतान की पत्रावली पर अनुमोदन नहीं देने, अधिशासी अधिकारी को बंधक बनाने के प्रयास और टेंडर प्रक्रिया में नियमों से छूट देने से जुड़े मामले भी सामने आए थे।

ओमकार गुप्ता के खिलाफ सभासद से मारपीट के एक मामले में तीन साल की सजा होने का भी उल्लेख किया गया है। फिलहाल अध्यक्ष पद रिक्त होने के बाद नगर पंचायत की जिम्मेदारी एसडीएम संजीव कुमार को सौंप दी गई है।

फास्ट न्यूज

भूमि विवाद में हमले का आरोपी गिरफ्तार

जलालपुर। शाहपुर फिरोजपुर गांव में भूमि विवाद को लेकर हुए हमले के मामले में पुलिस ने सोमवार को एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी रवींद्र कुमार यादव (48) को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

गांव निवासी दयाराम उपाध्याय ने पुलिस को दिए शिकायती पत्र में बताया था कि पांच अगस्त की शाम वह परिजनों के साथ खेत में काम करा रहे थे।

शीतला धाम में सावन की शाम भक्ति के रंग में रंगी

अंबेडकरनगर। सावन माह की संध्या पर शीतला धाम स्थित शीतला माता मठिया मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। मंदिर परिसर में हर-हर महादेव और राधे-राधे के जयकारे गूंजते रहे।

कार्यक्रम में राधा-कृष्ण का विशेष शृंगार किया गया। श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। इसके बाद भजन-संध्या में आशीष जैन, दिशांत गुप्ता, शुभम गुप्ता, सोनू जायसवाल, अभिषेक सोनकर, सौरभ सैनी, ऋतिक अग्रवाल, राज विश्वकर्मा, सोनू सोनकर, गोविंद निषाद और विकास निषाद ने भजन और मंत्रोच्चार प्रस्तुत किए।

तीन घंटे में बरामद हुआ 17 वर्षीय अमन

अंबेडकरनगर। जनता दर्शन में मिली शिकायत के बाद अकबरपुर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए लापता 17 वर्षीय किशोर को करीब तीन घंटे में सकुशल बरामद कर लिया। किशोर को अकबरपुर ओवरब्रिज के नीचे एनटीपीसी जाने वाली रेलवे लाइन के पास से बरामद किया गया। कोतवाली अकबरपुर क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने 21 अगस्त को जनता दर्शन के दौरान अपने 17 वर्षीय पुत्र अमन गुप्ता को बहला-फुसलाकर ले जाने के संबंध में प्रार्थना पत्र दिया था।

कुड़िया चितौना में जल जीवन मिशन की रफ्तार पर सवाल

बोरिंग हुई, फिर भी नहीं पहुंचा पानी!

तमसा संकेत, संवाददाता

अंबेडकरनगर। हर घर नल से जल पहुंचाने के लिए चल रही जल जीवन मिशन की योजना कुड़िया चितौना गांव में सवालों के घेरे में है। ग्रामीणों का कहना है कि परियोजना में बोरिंग तो करा दी गई, लेकिन इसके बाद जरूरी काम आगे नहीं बढ़े। मौके पर पंप हाउस और सोलर पैनल का काम दिखाई नहीं दे रहा है। इससे योजना की वास्तविक प्रगति को लेकर सवाल उठ रहे हैं।

ग्रामीणों के मुताबिक, परियोजना के कई जरूरी हिस्से अभी पूरे नहीं हुए हैं। इसके बावजूद अभिलेखों में दर्ज प्रगति को लेकर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि, कागजों में परियोजना की स्थिति क्या दर्ज है, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

ग्रामीणों का कहना है कि यदि परियोजना के जरूरी काम अभी अधूरे हैं तो माप पुस्तिका (एमबी), भुगतान और पूर्णता प्रमाणपत्र की जांच होनी चाहिए। इससे मौके के काम और अभिलेखों में दर्ज प्रगति के बीच स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

मौके पर पंप हाउस का निर्माण नहीं होने और सोलर पैनल नहीं लगाए जाने की बात सामने आ रही है। जलापूर्ति के लिए जरूरी पाइप-लाइन, टंकी और घरों तक कनेक्शन की स्थिति भी जांच का विषय है।

ग्रामीणों का कहना है कि योजना का उद्देश्य तभी पूरा होगा, जब सभी जरूरी ढांचे तैयार होने के बाद घरों तक पानी पहुंचे। ग्रामीणों ने संबंधित विभाग के अधिकारियों से मौके पर पहुंचकर परियोजना की जांच कराने की मांग की है।

महिला एवं बाल सम्मान कोष के पांच मामलों पर फैसला, एक को मंजूरी

जिला संचालन समिति की बैठक में एक प्रकरण खारिज

तमसा संकेत, संवाददाता

अंबेडकरनगर। उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष योजना के तहत लंबित पांच प्रकरणों पर मंगलवार को जिला संचालन समिति ने विचार किया। जिलाधिकारी ईशा प्रिया की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय कक्ष में हुई बैठक में एक प्रकरण को स्वीकृति दी गई, जबकि एक को अस्वीकृत कर दिया गया।

तीन प्रकरणों में एफएसएल और पैथोलॉजी रिपोर्ट उपलब्ध नहीं होने के कारण समिति ने उन्हें फिलहाल प्रतीक्षारत रखा है।

बैठक में कोष पोर्टल पर लंबित सभी पांच प्रकरणों के दस्तावेजों और उपलब्ध रिपोर्ट की समीक्षा की गई। समिति ने संबंधित अभिलेखों के आधार पर एक मामले को योजना के तहत स्वीकृति प्रदान की।

एक अन्य प्रकरण को निर्धारित आधार पर अस्वीकृत किया गया। वहीं, तीन मामलों में जरूरी एफए-सएल और पैथोलॉजी रिपोर्ट उपलब्ध नहीं होने के कारण अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका।

समिति स्तर पर लंबित तीन प्रकरणों को आवश्यक रिपोर्ट उपलब्ध होने तक प्रतीक्षारत रखा गया है। रिपोर्ट मिलने के बाद इन मामलों पर नियमानुसार आगे निर्णय लिया जाएगा।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला, अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी), अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी, जिला प्रोबेशन अधिकारी और संबंधित कर्मचारी मौजूद रहे।

पहले सीएनजी भराने की होड़ में भिड़े दो चालक

अकबरपुर-टांडा मार्ग पर लगा जाम

तमसा संकेत, संवाददाता

अंबेडकरनगर। अकबरपुर-टांडा मार्ग पर मंगलवार दोपहर पटेल नगर के पास सीएनजी पहले भराने को लेकर दो वाहन चालकों में विवाद हो गया। पेट्रोल पंप पर शुरू हुई कहासुनी देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। दोनों के सड़क पर आने से कुछ देर के लिए यातायात प्रभावित हुआ।

बताया गया कि दोनों चालक सीएनजी भराने के लिए पेट्रोल पंप पर कतार में खड़े थे। पहले सीएनजी भराने की बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई। विवाद बढ़ने पर दोनों सड़क पर आ गए और मारपीट शुरू कर दी। सड़क पर मारपीट होने से अकबरपुर-टांडा मार्ग पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो गई। कुछ ही देर में सड़क पर वाहनों की कतार लग गई और जाम जैसी स्थिति बन गई। मारपीट होते देख आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। स्थानीय लोगों ने दोनों चालकों को अलग किया। इसके बाद स्थिति शांत हुई और यातायात सामान्य हो गया।

घटना के दौरान किसी व्यक्ति ने मारपीट का वीडियो बना लिया। बताया जा रहा है कि वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। वीडियो में दोनों चालकों के बीच सड़क पर हाथापाई होती दिखाई दे रही है। मामले में समाचार लिखे जाने तक किसी भी पक्ष की ओर से पुलिस को लिखित शिकायत नहीं दी गई थी।

भूमि एवं जल संरक्षण समिति की बैठक में कृषि योजनाओं की समीक्षा

31 अगस्त से पहले करा लें फसल बीमा वरना छूट सकता है योजना का लाभ

तमसा संकेत, संवाददाता

अंबेडकरनगर। खरीफ फसलों को लेकर किसानों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2026 निर्धारित है। इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने पात्र किसानों को समय से योजना से जोड़ने के निर्देश दिए हैं। बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी ईशा प्रिया की अध्यक्षता में जिला भूमि एवं जल संरक्षण समिति और जिला मिशन समिति की बैठक हुई। इसमें कृषि विभाग से जुड़ी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा के साथ फसल बीमा योजना पर भी चर्चा हुई।

बैठक में खेत तालाब योजना, पंडित दीन दयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना और आरकेवीवाई-रफ्तार/आरएडी योजना की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने योजनाओं के तहत चल रहे कार्यों, किसानों को मिल रही सुविधाओं और प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि योजनाओं के लिए पात्र किसानों का चयन कर उन्हें समय से लाभ दिया जाए। योजनाओं के क्रियान्वयन में गुणवत्ता और पारदर्शिता का विशेष ध्यान रखने को भी कहा गया।

जिलाधिकारी ने कहा कि किसान हित से जुड़ी योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। पात्र किसानों को योजनाओं की जानकारी समय पर मिले और उन्हें निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार लाभ दिलाया जाए।

बैठक में ये रहे मौजूद

बैठक में विधान परिषद सदस्य हरिओम पांडेय, कटेहरी विधायक धर्मराज निषाद, जिला पंचायत प्रशासक साधू वर्मा, मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला, उप कृषि निदेशक, जिला कृषि अधिकारी एवं भूमि संरक्षण अधिकारी समेत संबंधित विभागों के अधिकारी और लाभार्थी किसान मौजूद रहे।

फसल खराब हुई तो बीमा से मिलेगा लाभ

बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि अधिक से अधिक पात्र किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जोड़ा जाए। प्राकृतिक आपदा या अन्य कारणों से फसल को नुकसान होने की स्थिति में पात्र किसानों को योजना के तहत लाभ मिल सकेगा। जिलाधिकारी ने किसानों तक योजना की जानकारी पहुंचाने और अंतिम तिथि से पहले बीमा कराने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार कराने को कहा।

मेडिकल कॉलेज में नशामुक्ति केंद्र शुरू, गंभीर मानसिक रोगों के इलाज की भी बढ़ी सुविधा

ईसीटी और मल्टी बिहेवियरल सेक्स थेरेपी की सुविधा भी शुरू

तमसा संकेत, संवाददाता

अंबेडकरनगर। महामाया राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज में मंगलवार को नशे की लत से जूझ रहे मरीजों के उपचार के लिए एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी (ATF) विंग शुरू किया गया। प्रधानाचार्य डॉ. मुकेश यादव ने फीता काटकर केंद्र का उद्घाटन किया। इसके साथ ही गंभीर मानसिक रोगियों के उपचार के लिए इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी (ECT) और यौन स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए मल्टी बिहेवियरल सेक्स थेरेपी मशीन की सुविधा भी शुरू की गई। एटीएफ विंग में शराब, तंबाकू, सिगरेट, स्मैक, भांग और गांजा समेत विभिन्न प्रकार के नशों की निर्भरता से प्रभावित मरीजों को उपचार और चिकित्सकीय परामर्श मिलेगा। केंद्र में मरीजों की जरूरत के अनुसार काउंसलिंग और उपचार की व्यवस्था भी की गई है।

इस सुविधा से अंबेडकरनगर और आसपास के क्षेत्रों के मरीजों को नशे की समस्या के लिए जिले में ही चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी।

मेडिकल कॉलेज में ईसीटी की सुविधा शुरू होने से गंभीर मानसिक रोगों से पीड़ित मरीजों के उपचार का विकल्प बढ़ा है। वहीं, मल्टी बिहेवियरल सेक्स थेरेपी मशीन के माध्यम से यौन स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के लिए चिकित्सकीय परामर्श और उपचार उपलब्ध कराया जाएगा।

कॉलेज प्रशासन ने बताया कि इन सुविधाओं का उद्देश्य मरीजों को विशेषज्ञ चिकित्सा उपलब्ध कराना और अप्रमाणित उपचार से बचने के लिए सही चिकित्सकीय सलाह तक पहुंच सुनिश्चित करना है।

एटीएफ विंग को एनडीडी-टीसी, एम्स नई दिल्ली के सहयोग और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के समर्थन से शुरू किया गया है। मानसिक रोग विभागाध्यक्ष एवं एटीएफ नोडल अधिकारी डॉ. अमित कुमार गुप्ता के निर्देशन में केंद्र की व्यवस्थाएं तैयार की गईं।

एम्स नई दिल्ली से प्रशिक्षण प्राप्त काउंसलर विनोद कनौजिया, काउंसलर प्रियम खरे, स्टाफ नर्स अनुराग त्रिपाठी और डाटा मैनेजर स्वीटी शर्मा ने केंद्र की शुरुआत से जुड़ी तैयारियों में काम किया।

खेत में मिला चारा काटने गए व्यक्ति का शव, मौत की वजह पर जांच

बीबीपुर गांव में घर से 500 मीटर दूर मिला रणविजय यादव का शव

तमसा संकेत, संवाददाता

अंबेडकरनगर। कटका थाना क्षेत्र के बीबीपुर गांव में मंगलवार सुबह खेत में एक व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान रणविजय यादव के रूप में हुई। वह सोमवार शाम चारा काटने के लिए खेत गए थे। देर रात तक घर नहीं लौटने पर परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की थी।

परिजनों के मुताबिक, रणविजय सोमवार शाम खेत के लिए निकले थे। काफी देर तक वापस नहीं आने पर परिवार के लोगों ने आसपास तलाश की, लेकिन रात में उनका पता नहीं चल सका।

मंगलवार सुबह परिजनों ने दोबारा तलाश शुरू की। इस दौरान घर से करीब 500 मीटर दूर खेत में रणविजय का शव पड़ा मिला। सूचना मिलते ही ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए। ग्रामीणों ने किसी जीव-जंतु के काटने से मौत होने की आशंका जताई है। हालांकि, इसकी पुष्टि नहीं हुई है। मौत का वास्तविक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट होगा।

शव मिलने की जानकारी पर ग्राम प्रधान संतोष कुमार गुप्ता ने 112 पर सूचना दी। इसके बाद 112 पुलिस टीम और कटका थाना प्रभारी अक्षय पटेल मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। रणविजय यादव दो भाइयों में सबसे बड़े थे। परिवार में पत्नी माधुरी देवी और दो बेटे अरुण कुमार व राहुल कुमार हैं। उनके पिता बगेदू यादव का पहले ही निधन हो चुका है, जबकि मां जीवित हैं।

जांच : सुरहुरपुर बाजार के पास हुआ हादसा टक्कर के बाद मौके पर जुटे लोग

पुल पर आमने-सामने भिड़े स्कूली बस और चीनी लदे ट्रेलर

- बच्चों के सुरक्षित मिलने पर परिजनों को मिली राहत
- पुलिस ने चालकों से की पूछताछ
- टक्कर कैसे हुई, पुलिस जुटा रही जानकारी

तमसा संकेत, संवाददाता

अंबेडकरनगर। मालीपुर थाना क्षेत्र में मंगलवार सुबह बड़ा सड़क हादसा टल गया। सुरहुरपुर बाजार के आगे नदी पुल के पास रेडिएंट एकेडमी की स्कूली बस और चीनी लदे ट्रेलर की आमने-सामने टक्कर हो गई। बस में करीब 25 बच्चे सवार थे। हादसे के बाद मौके पर पहुंचे लोगों ने बच्चों को बस से बाहर निकाला। सभी बच्चे सुरक्षित बताए गए हैं। किसी के घायल होने की सूचना नहीं है।

हादसे की जानकारी मिलते ही बच्चों के अभिभावकों में चिंता फैल गई। कुछ ही देर में बच्चों के सुरक्षित होने की सूचना मिलने पर परिजनों को राहत मिली।

स्थानीय लोगों ने बच्चों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने में मदद की। हादसे में किसी बच्चे या चालक के घायल होने की सूचना नहीं है।

सूचना मिलते ही मालीपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों वाहनों की स्थिति देखी और चालकों से पूछताछ की। पुलिस के अनुसार, बस में सवार सभी करीब 25 बच्चे और दोनों वाहनों के चालक सुरक्षित हैं।

दुर्घटना के बाद मार्ग पर कुछ समय के लिए आवागमन प्रभावित रहा। मौके पर लोगों की भीड़ भी जुट गई। पुलिस हादसे के वास्तविक कारण का पता लगाने में जुटी है। दुर्घटना से जुड़े तथ्यों और परिस्थितियों की जांच की जा रही है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

जलालपुर से बच्चों को लेकर जा रही थी बस

जलालपुर स्थित रेडिएंट एकेडमी की बस मंगलवार सुबह बच्चों को लेकर स्कूल जा रही थी। इसी दौरान मालीपुर की ओर से चीनी लदा ट्रेलर शाहगंज की तरफ जा रहा था। सुरहुरपुर बाजार के आगे नदी पुल के पास दोनों वाहन आमने-सामने आ गए और टक्कर हो गई। टक्कर के बाद बस में सवार बच्चों के बीच अफरातफरी मच गई। आसपास के लोगों ने तत्काल मौके पर पहुंचकर बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला।

सूने मकान का ताला तोड़कर 10 लाख के जेवरात और सामान ले गए चोर

तमसा संकेत, संवाददाता

अंबेडकरनगर। अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के सीहमई कारीरात गांव में चोरों ने बंद मकान को निशाना बनाकर करीब 10 लाख रुपये के जेवरात और अन्य कीमती सामान पर हाथ साफ कर दिया। परिवार की महिला के घर लौटने पर मंगलवार को चोरी की जानकारी हुई। सूचना मिलने पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

गांव निवासी भरतमणि तिवारी के मुताबिक, घर में रहने वाली गीता तिवारी दो दिन पहले मायके गई थीं। घर पर किसी के नहीं होने का फायदा उठाकर चोरों ने वारदात को अंजाम दिया।

मंगलवार को गीता तिवारी घर लौटीं तो कमरे का ताला टूटा मिला। अंदर जाकर देखा तो अलमारियों और बक्सों का सामान बिखरा था। बेड का लॉकर भी टूटा हुआ था।

पीड़ित परिवार के अनुसार, चोरों ने दो अलमारियों, तीन बक्सों और बेड के लॉकर को तोड़कर सामान खंगाला। चोर करीब 15 ग्राम के कान के झुमके, 12 ग्राम का कान का झाला, 20 ग्राम का मंगलसूत्र, दो अंगूठियां, नाक की कील, सात जोड़ी पायल और एक छागल समेत अन्य सामान ले गए।

- सीहमई कारीरात में दो दिन से बंद था घर, अलमारियों, बक्सों और बेड का लॉकर तोड़कर की चोरी

परिवार ने चोरी गए सामान की कुल कीमत करीब 10 लाख रुपये बताई है। भरतमणि तिवारी उत्तराखंड रोडवेज विभाग में यातायात निरीक्षक के पद पर कार्यरत हैं।

सम्पादकीय

निरंकुश साइबर ठग

साइबर धोखाधड़ी में लिप्त दो लोगों की मुंबई से गिरफ्तारी के बाद जिस तरह यह उजागर हुआ कि उनकी ओर से ठगी गई रकम सैकड़ों करोड़ों रुपये हो सकती है, वह इसका सूचक है कि डिजिटल अरेस्ट, निवेश के लालच और अन्य तरीकों से साइबर धोखाधड़ी करने वाले कितने अधिक बेलगाम हो गए हैं।

ईडी की ओर से गिरफ्तार किए गए इन लोगों पर मनी लांड्रिंग के तहत भी मुकदमा चलाया जाएगा, क्योंकि वे धोखाधड़ी से हासिल धनराशि को विदेशी मुद्रा में बदलकर विदेश भेज देते थे। इस नेटवर्क की व्यापकता का पता इससे चलता है कि यह 20 राज्यों में फैला था और इसे चार सौ खातों के जरिये संचालित किया जा रहा था। इस गिरोह के शिकार लोगों की संख्या सैकड़ों में है।

इसका मतलब है कि साइबर धोखाधड़ी का काम एक तरह से एक उद्यम की तरह चलाया जा रहा था। यह संगठित अपराधियों की ओर से की जाने वाली आनलाइन डकैती ही है। हैरानी नहीं कि देश में साइबर धोखाधड़ी करने वाले इस तरह के और भी बड़े गिरोह हों। वैसे भी छोटे-मोटे गिरोहों की तो कोई गिनती ही नहीं है। उनकी सक्रियता का पता इससे चलता है कि लगभग हर दिन देश के किसी न किसी हिस्से से साइबर ठगी का कोई मामला सामने आता है।

विडंबना यह है कि बहुत कम मामलों में पुलिस ठगों तक पहुंच पाती है। इससे भी बड़ी समस्या है कि कुछ ही मामलों में धोखाधड़ी करके हड़पी गई राशि पीड़ित व्यक्तियों को मिल पाती है। साइबर ठगों तक पुलिस की मुश्किल से पहुंच का एक कारण यह है कि वे दूरदराज से और कई बार तो विदेश में बैठकर ठगी करते हैं।

साइबर ठगी के बढ़ते मामलों का संज्ञान सुप्रीम कोर्ट भी ले चुका है और वह कुछ मामलों की जांच सीबीआइ को भी सौंप चुका है, लेकिन यह कहना कठिन है कि साइबर अपराधियों पर कोई प्रभावी लगाम लग पा रही है। वे नए-नए तरीकों से ठगी करने में सफल हैं। इसका प्रमाण यह भी है कि साइबर ठगी के जरिये लोगों से हड़पी गई राशि बढ़ती ही जा रही है। वैसे तो बैंकों में जमा धन की हेराफेरी पहले भी होती थी, लेकिन इसके मामले बहुत कम होते थे और अधिकतर मामलों में धोखाधड़ी करने वाले पकड़े जाते थे, लेकिन साइबर अपराधी बिल्कुल निरंकुश दिख रहे हैं।

यह मानने के अच्छे-भले कारण हैं कि साइबर ठग पुलिस से दो कदम आगे हैं। एक ऐसे समय जब आनलाइन बैंकिंग और डिजिटल लेनदेन का चलन बढ़ता जा रहा है, तब साइबर ठगी पर प्रभावी अंकुश न लग पाना गंभीर चिंता की बात है। सरकार को इस पर गंभीरता से ध्यान देना होगा कि साइबर अपराधों की छानबीन करने वाली पुलिस और अन्य एजेंसियां तकनीकी कौशल में कहीं अधिक समर्थ बनें। अभी वे डाल-डाल हैं तो साइबर ठग पात-पात। वे इतने शातिर हैं कि अच्छे-खासे पढ़े-लिखे लोग भी उनकी चपेट में आ जा रहे हैं।

विकसित भारत की राह में जर्जर शिक्षा व्यवस्था सबसे बड़ा सवाल

66

नीति आयोग की हालिया रिपोर्ट एक और महत्वपूर्ण तस्वीर सामने रखती है। 2014-15 में देश में 11.07 लाख सरकारी स्कूल थे, जो 2024-25 में घटकर 10.13 लाख रह गए। इसके विपरीत निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों की संख्या 2.88 लाख से बढ़कर 3.39 लाख हो गई।

भारत आज वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है। एक शिक्षक, टूटती दीवारें और घटते सरकारी स्कूल-क्या शिक्षा के बिना 2047 का सपना पूरा होगा? दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में देश की प्रगति, डिजिटल क्रांति, अंतरिक्ष उपलब्धियां, आधारभूत ढांचे का विस्तार और वैश्विक मंच पर बढ़ता प्रभाव निश्चित रूप से गौरव का विषय हैं। लेकिन इसी चमकदार तस्वीर के पीछे यदि हम सरकारी स्कूलों की ओर देखें तो एक दूसरा भारत दिखाई देता है-ऐसा भारत जहां हजारों बच्चे आज भी पर्याप्त शिक्षकों, सुरक्षित भवन, स्वच्छ पेयजल, शौचालय, बिजली और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सवाल यह है कि जिस शिक्षा-व्यवस्था पर विकसित भारत की नींव रखी जानी है, उसकी बुनियाद ही कमजोर होगी तो 2047 का भारत कितना मजबूत होगा? सरकारी आंकड़े इस चिंता को और गंभीर बनाते हैं। यूडीआईएसई प्लस 2024-25 के अनुसार देश में 1,04,125 स्कूल ऐसे हैं जहां केवल एक शिक्षक कार्यरत है और इन स्कूलों में करीब 33.77 लाख विद्यार्थी पढ़ते हैं। यानी एक शिक्षक को कई कक्षाओं, अनेक विषयों और प्रशासनिक जिम्मेदारियों के बीच बच्चों की शिक्षा संभालनी पड़ रही है। यह केवल संख्या नहीं, बल्कि उन लाखों बच्चों के भविष्य की कहानी है, जिनके लिए सरकारी स्कूल शिक्षा का सबसे सुलभ और कई बार एकमात्र माध्यम हैं। विडंबना यह है कि उसी देश में हम विश्वस्तरीय विश्वविद्यालयों, आईआईटी, आईआईएम, मेडिकल संस्थानों और अत्याधुनिक शिक्षण परिसरों की चर्चा करते हैं, लेकिन गांव के उस बच्चे की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं देते जो टूटी छत के नीचे बैठकर भविष्य के सपने देख रहा है। कहीं शिक्षक एक है और कक्षाएं पांच। कहीं विद्यालय भवन जर्जर है, कहीं पानी नहीं, कहीं शौचालय नहीं, कहीं बिजली और पंखे नहीं। हाल के महीनों में उत्तर प्रदेश के अनेक जिलों में विद्यार्थियों को अधिक शिक्षक, बेहतर भोजन, पेयजल, पंखे और बुनियादी सुविधाओं की मांग को लेकर सड़कों पर उतरना पड़ा। फतेहपुर में तो लगभग एक हजार विद्यार्थियों ने जर्जर कक्षाओं, रिसती छतों और सुरक्षित पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए प्रदर्शन किया। यह स्थिति केवल किसी एक राज्य अथवा किसी एक सरकार की विफलता नहीं है। यह वर्षों से चली आ रही उस प्रशासनिक सोच का परिणाम है जिसमें शिक्षा को प्राथमिकता तो भाषणों में दी गई, लेकिन उसकी गुणवत्ता और जवाबदेही को शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में स्थान नहीं मिला। शिक्षा विभागों में अधिकारियों और कर्मचारियों की बड़ी व्यवस्था है, बजट है, योजनाएं हैं, समितियां हैं, निरीक्षण तंत्र है-फिर भी एक शिक्षक वाले एक लाख से अधिक स्कूल कैसे बने रहे? यह सवाल केवल सरकार से नहीं, पूरे प्रशासनिक तंत्र से पूछा जाना चाहिए। निश्चित रूप से तस्वीर पूरी तरह निराशाजनक भी नहीं है। यूडीआईएसई प्लस के अनुसार 2024-25 में देश में कुल 14.71 लाख स्कूल, करीब 24.69 करोड़ विद्यार्थी और एक करोड़ से अधिक शिक्षक हैं। सरकारी स्कूलों की संख्या 10.13 लाख है, जबकि निजी मान्यता प्राप्त स्कूल करीब 3.40 लाख हैं। सरकार के आंकड़े यह भी बताते हैं कि एकल-शिक्षक स्कूलों की संख्या 2023-24 के 1,10,971 से घटकर 2024-25 में 1,04,125 हुई है और कंप्यूटर सुविधा वाले स्कूलों का अनुपात 57.2 प्रतिशत से बढ़कर 64.7 प्रतिशत हुआ है। इन सुधारों को स्वीकार करना चाहिए, लेकिन इन्हें अंतिम उपलब्धि मान लेना आत्मसंतोष होगा। क्योंकि शिक्षा की असली कसौटी भवन, कंप्यूटर या आंकड़े नहीं, बच्चे की सीखने की क्षमता और उसके भविष्य का निर्माण है। यह परिवर्तन केवल स्कूलों की संख्या का उतार-चढ़ाव नहीं है, यह अभिभावकों की बदलती पसंद और सरकारी शिक्षा में घटते विश्वास का संकेत भी है। सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि जब सरकार के पास भवन है, जमीन है, प्रशिक्षित शिक्षक हैं, वेतन देने की क्षमता है और विशाल प्रशासनिक तंत्र है, तब सरकारी स्कूल निजी स्कूलों से पीछे क्यों हैं? निजी स्कूलों की आलोचना करना आसान है, लेकिन यह भी देखना होगा कि अभिभावक अपनी सीमित आय में फीस देकर भी निजी स्कूल क्यों चुन रहे हैं। इसका उत्तर सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता, अनुशासन, नियमितता, अंग्रेजी एवं तकनीकी शिक्षा, अभिभावक संवाद और सीखने के वातावरण में छिपा है। एसीईआर के आंकड़े भी इस अंतर को रेखांकित करते हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 2024 में कक्षा 3 के बच्चों में कक्षा 2 स्तर का पाठ पढ़ पाने वालों का अनुपात सरकारी स्कूलों में 23.4 प्रतिशत था, जबकि निजी स्कूलों में 35.5 प्रतिशत। कक्षा 5 में भी सरकारी स्कूलों का आंकड़ा 44.8 प्रतिशत और निजी स्कूलों का 59.3 प्रतिशत रहा। यानी समस्या केवल स्कूल भवन की नहीं, सीखने के परिणामों की भी है।

इसी के समानांतर उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तस्वीर भी चिंता पैदा करती है। पेपर लीक, परीक्षा में अनियमितता, भर्ती में देरी और युवाओं के आंदोलनों की खबरें लगातार सामने आती रही हैं। 2026 में परीक्षा संबंधी विवादों ने विद्यार्थियों और अभ्यर्थियों में असंतोष को व्यापक बनाया। इसका अर्थ यह है कि समस्या शिक्षा-व्यवस्था के निचले स्तर से लेकर उच्च स्तर तक फैली हुई है। प्राथमिक स्कूल में कमजोर नींव, माध्यमिक शिक्षा में गुणवत्ता का संकट और उच्च शिक्षा तथा प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता का सवाल-इन सबको अलग-अलग देखकर समाधान नहीं निकलेगा। सरकारी स्कूल वास्तव में भारत की सामाजिक समानता का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम हैं। इन स्कूलों में ग्रामीण परिवारों, श्रमिकों, गरीबों, वंचित वर्गों और निम्न आय वाले परिवारों के बच्चे बड़ी संख्या में पढ़ते हैं। यदि इन विद्यालयों की गुणवत्ता गिरती है तो सबसे अधिक नुकसान उसी वर्ग को होता है जिसके पास महंगे निजी स्कूलों का विकल्प नहीं है। इसलिए सरकारी स्कूलों की बदहाली केवल शिक्षा का संकट नहीं, सामाजिक न्याय का संकट भी है।

ललित गर्ग

गंगा की पारिस्थितिकी...

कुमार कृष्णन

फरक्का और बिहार के गंगा जल का सवाल

फरक्का बैराज और भारत-बांग्लादेश गंगा जल बंटवारा संधि एक बार फिर बहस के केंद्र में है। 12 दिसंबर 1996 को भारत और बांग्लादेश के बीच हुई गंगा जल बंटवारा संधि की तीस वर्ष की अवधि दिसंबर 2026 में पूरी हो रही है। इसलिए इसकी समीक्षा केवल पुरानी संधि को आगे बढ़ाने का प्रश्न नहीं है। यह तय करने का अवसर भी है कि बदलती जलवायु, बढ़ती आबादी, कृषि, उद्योग, पेयजल, नौवहन और पर्यावरणीय जरूरतों के बीच गंगा के पानी को लेकर अगली व्यवस्था कैसी होगी।

जनता दल (यू) के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य संजय कुमार झा ने मांग की है कि 1996 की संधि को उसी रूप में आगे बढ़ाने के बजाय गंगा बेसिन पर निर्भर राज्यों की वर्ष 2050 तक की जल जरूरतों का वैज्ञानिक आकलन किया जाए। दूसरी ओर बक्सर के सांसद सुधाकर सिंह ने इस दृष्टिकोण पर सवाल उठाते हुए बिहार की पुरानी शिकायतों और 24 जनवरी 1997 की सचिव-स्तरीय बैठक के दस्तावेज का हवाला दिया है। दोनों पक्षों की राजनीतिक भाषा अलग है, लेकिन उनके बीच एक साझा प्रश्न है—गंगा के जल पर बिहार की वर्तमान और भविष्य की जरूरतों का आकलन किस आधार

पर होगा? फरक्का बैराज का निर्माण मूलतः हुगली नदी में पर्याप्त जल प्रवाह बनाए रखने और कोलकाता बंदरगाह में गाद की समस्या कम करने के उद्देश्य से किया गया था। 1975 में इसके चालू होने के बाद गंगा के पानी को फीडर नहर के माध्यम से भागीरथी-हुगली तंत्र की ओर मोड़ा गया। लेकिन नदी पर बना कोई बड़ा अवरोध केवल पानी के बंटवारे को प्रभावित नहीं करता। नदी पानी के साथ गाद, पोषक तत्व, मछलियां और जलीय जीवन भी बहाती है। प्रवाह में परिवर्तन नदी की आकृति, तलछट के वितरण और जलीय पारिस्थितिकी को प्रभावित कर सकता है।

फरक्का के दुष्परिणामों को सबसे पहले भांपने वालों में नदी के मछुआरे थे। गंगा मुक्ति आंदोलन से जुड़े अनिल प्रकाश बताते हैं कि करीब 35 वर्ष पहले जब वे मछुआरों को गंगा पर जमींदारों के कब्जे के खिलाफ संगठित करने के लिए गांव-गांव घूम रहे थे, तो मछुआरे उनसे फरक्का को तोड़ने की मांग करते थे। तब उन्हें समझ नहीं आता था कि मछुआरे ऐसा क्यों कह रहे हैं। बाद में भागलपुर विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक के. एस. बिलग्रामी और जे. एस. दत्ता मुंशी के शोध का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि मछुआरों की आशंका निराधार नहीं थी। उनके अनुसार इन वैज्ञानिकों ने गंगा की पारिस्थितिकी पर शोध किया था।

अनिल प्रकाश का दावा है कि फरक्का के बाद गंगा और उसकी सहायक नदियों में मछलियों की उपलब्धता में भारी कमी आई और इसके कारण लाखों मछुआरों की आजीविका प्रभावित हुई। इन दावों की स्वतंत्र वैज्ञानिक जांच जरूरी है, लेकिन मछुआरों के अनुभव को महज लोकविश्वास कहकर खारिज करना भी उचित नहीं। नदी में होने वाला बदलाव सबसे पहले वही समुदाय महसूस करता है जिसकी रोजी-रोटी सीधे उसके प्रवाह और जलीय जीवन से जुड़ी होती है।

कहलगांव के योगेन्द्र सहनी बताते हैं कि कागजी टोला मछुआरा बस्ती से करीब चालीस प्रतिशत लोग रोजगार की तलाश में पलायन कर चुके हैं। अगर यह अनुभव व्यापक क्षेत्र में भी दिखाई देता है तो यह केवल मत्स्य उत्पादन का नहीं, बल्कि ग्रामीण रोजगार और सामाजिक संरचना का प्रश्न है। गंगा मुक्ति आंदोलन से जुड़े उदय की बात इस बहस को और स्पष्ट करती है—"नदी पर पहला हक मछुआरों का है। उसके बाद किसान और आस्थावानों का।" उनका कहना है कि मछुआरे नदी को जिस रूप में देखते हैं, वह दूसरे लोगों के नदी-बोध से अलग है।

गंगा की पारिस्थितिकी में मछलियों के साथ गांगेय डॉल्फिन जैसी महत्वपूर्ण प्रजातियां भी हैं। हिलसा जैसी मछलियों का प्रवास भी नदी की पारिस्थितिक निरंतरता से जुड़ा है। इसलिए भविष्य की जल नीति में पर्यावरणीय प्रवाह को केंद्रीय स्थान देना होगा। नदी में केवल न्यूनतम मात्रा में पानी छोड़ना पर्याप्त नहीं होगा।

इस परियोजना...

इंजेश सिंह

बुंदेलखण्ड के रोहिणी, जामनी एवं सजनाम बाँध परियोजना के जीर्णोद्धार से किसानों के खेतों तक पहुँचा पानी

उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र को वर्तमान सरकार के पूर्व लंबे समय से जल संकट और सिंचाई की समस्याओं का सामना करना पड़ता था। वर्षा पर निर्भर कृषि, सूखे की स्थिति तथा जल संसाधनों के सीमित उपयोग के कारण इस क्षेत्र के किसानों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। इन चुनौतियों से निपटने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा विश्व बैंक पोषित उत्तर प्रदेश वाटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग परियोजना (द्वितीय चरण) के अंतर्गत रोहिणी, जामनी एवं सजनाम बाँधों से संबंधित नहरों के पुनरुद्धार और आधुनिकीकरण का कार्य किया गया। इस परियोजना ने न केवल सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ किया है, बल्कि जल संरक्षण, कृषि उत्पादन में वृद्धि तथा ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन की सुविधाओं को भी बेहतर बनाया है। इस परियोजना के सफल क्रियान्वयन से बुंदेलखंड के हजारों किसानों को सीधा लाभ मिला है।

परियोजना की पृष्ठभूमि एवं जीर्णोद्धार का कार्य-

बुंदेलखण्ड के जनपद ललितपुर में दशको पूर्व रोहिणी, जामनी एवं सजनाम नदियों पर सिंचाई पेयजल हेतु बनाई गयी बांध परियोजना क्षेत्रीय लोगों के लिए जल की कमी दूर करती थी। बांध के नीचे तथा नहरों के पुराने और जर्जर होने के कारण बड़ी मात्रा में पानी रिसकर नष्ट हो जाता था। परिणामस्वरूप नहरों के अंतिम छोर तक पानी नहीं पहुँच पाता था और किसानों को पर्याप्त सिंचाई सुविधा नहीं मिल पाती थी। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए रोहिणी, जामनी और सजनाम बाँधों से निकलने वाली नहरों के व्यापक सुधार और पुनर्निर्माण का कार्य प्रारंभ किया गया। इस परियोजना का उद्देश्य जल के बेहतर प्रबंधन के साथ-साथ सिंचाई व्यवस्था को अधिक प्रभावी और आधुनिक बनाना था।

इस महत्त्वाकांक्षी परियोजना के अंतर्गत महरौनी विधानसभा क्षेत्र के महरौनी, मड़ावरा तथा पाली तहसील क्षेत्रों में नहरों के पुनरुद्धार के अनेक कार्य संपन्न किए गए। इनमें प्रमुख रूप से नहरों की लाइनिंग का कार्य, नहरों के किनारे स्थित सर्विस रोड का पुनर्निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण, नहरों पर बने पुलों एवं अन्य पक्के ढाँचों की मरम्मत, जर्जर संरचनाओं का नवीनीकरण, जल निकासी प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए नई संरचनाओं का निर्माण और नहरों के रखरखाव और संचालन को अधिक प्रभावी बनाया गया। इन कार्यों से नहरों की कार्यक्षमता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है और जल की बर्बादी में भी कमी आई है।

परियोजना के मुख्य उद्देश्य

इस परियोजना का सबसे प्रमुख उद्देश्य नहरों के अंतिम छोर तक किसानों को सिंचाई हेतु पानी पहुँचाना था, जिससे प्रत्येक किसान को समान रूप से सिंचाई का लाभ मिल सके। इसके अलावा अन्य महत्त्वपूर्ण उद्देश्य भी निर्धारित किए गए। इनमें बाँधों में संचित जल का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए नहरों की लाइनिंग की गई।

रोज वही कोशिश

आधुनिक भौतिक चकाचौंध के इस युग मानव ने जन्म लिया पाँव से चला व कुछ समझने लगा तो परिवार के द्वारा यह संस्कार देने शुरू कर दिये जाते हैं की देखो कक्षा में यह कैसे प्रथम आया हैं और तुमको आना है । वह रोज़ पढ़ाई करता है और अच्छे से अच्छे नम्बर लाता हैं तुमको भी ऐसे ही पढ़ाई करना हैं आदि - आदि बातें कूट - कूट कर मासूम सी जान में भर देते हैं जिससे उसको आगे की तरीक़े से वास्तव में ज़िन्दगी की राह पकड़नी हैं वो अपनी समझ -बुझ से नहीं पकड़ पाता हैं थोपी हुई राह पर चल पड़ता हैं । अब धीरे - धीरे बच्चा बड़ा होता जाता हैं तो उसको पिता आदि से यह सूनने को मिलता हैं की मैंने इतने लाख , करोड़ आदि अर्थ कमायें हैं वर्ष भर में जब तुम कमाओगे तो व लाओगे तो मालूम पड़ेगा आदि - आदि इस तरह की बातें करने शुरू कर देते हैं । बचपन छिना व बच्चों के खेलकूद का समय जो होता हैं वो छिन लिया । सूनी सुनाई व एक तरीक़े से थोपी हुई राह पर वो आगे चल पड़ा । डिग्री व प्रोफ़ेशनल डिग्री जो आयी उसके हिसाब से जीवन की राह में वो चल पड़ा । परिवार बँधा तो वो ही रोज़ नित - नियम का क्रम चलना शुरू हों गया रोज़ सुबह इतने बजे उठना , करना व दिन में यह करना व रात को इतने बजे व ऐसे सो जाना आदि - आदि । अभी के जीवन में धार्मिक शब्द देखना - सूनना आदि कम व नहीं रहा । अब मैं एक घटना लेता हुँ ।मैं मुनि श्री के दर्शन करने गया तो मुनिवर के किसी ने दर्शन किये तो मुनिवर ने कहा की दर्शन तो व ख़ुद के लियें समय तो रोज़ निकाल लिया करों तो उसने कहा की ख़ुद के लियें ही तो रोज़ की दौड़ - धूप मैं कर रहा हूँ व दर्शन का समय जैसे मुझे मिलता हैं वैसे कर लेता हुँ तो मुनिवर ने कहा की आत्मा के लियें रोज़ कितना समय देते हों तो उसने कहा की आत्मा के लियें ही तो यह रोज़ की दौड़ - धूप कर रहा हूँ और क्या चाहिये आत्मा को ।

› प्रदीप छाजेड़

जरा हटके

पंजीयन से लेकर ...

डॉ0 सीमा गुप्ता

श्रमिक कल्याण योजनाओं से फिरोजाबाद में संवरता निर्माण कामगार परिवारों का भविष्य

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के निर्माण श्रमिकों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान एवं व्यापक सुरक्षा कवच के लिए संचालित कल्याणकारी योजनाएं धरातल पर अत्यंत प्रभावी और परिवर्तनकारी सिद्ध हो रही हैं। राज्य में निर्माण गतिविधियों से जुड़े करोड़ों कर्मकारों के श्रम का सम्मान करते हुए प्रदेश सरकार ने उनके जीवन चक्र के प्रत्येक संवेदनशील पड़ाव पर वित्तीय संबल प्रदान करने की एक सुदृढ़ व्यवस्था स्थापित की है। 'सुरक्षित श्रम, सशक्त श्रमिक' के संकल्प के साथ संचालित इन योजनाओं का उद्देश्य केवल तात्कालिक राहत देना नहीं, बल्कि विपत्ति के समय श्रमिक परिवारों को आत्मनिर्भरता की मुख्यधारा में बनाए रखना है। कांच उद्योग एवं निर्माण क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने वाले जनपद फिरोजाबाद में इन नीतियों के सुव्यवस्थित क्रियान्वयन से अनेक संकटग्रस्त परिवारों के जीवन में स्थायित्व, सम्मान और नई आशा का संचार हुआ है। जनपद फिरोजाबाद की सामाजिक एवं आर्थिक संरचना में निर्माण कामगारों का विशेष योगदान रहा है। दिन-रात पसीना बहाकर विकास की आधारशिला रखने वाले इन श्रमिकों के सामने आकस्मिक दुर्घटना अथवा मुखिया के असामयिक निधन की स्थिति में गंभीर आर्थिक संकट खड़ा हो जाता है। ऐसी ही एक संवेदनशील परिस्थिति में फिरोजाबाद की निवासी अनीता के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, जब उनके पति, जो एक पंजीकृत निर्माण मजदूर थे, का अचानक निधन हो गया। परिवार के एकमात्र कमाऊ सदस्य के चले जाने से घर के दैनिक भरण-पोषण, बच्चों के लालन-पालन और विशेषकर विवाह योग्य पुत्री के भविष्य को लेकर अनीता के सामने विकट चुनौती उत्पन्न हो गई थी। चारों ओर घोर निराशा और अनिश्चितता के उस अंधकारमय दौर में प्रदेश सरकार की सामाजिक सुरक्षा नीतियों ने इस पीड़ित परिवार के लिए जीवनरक्षक संबल की भूमिका निभाई। जिला प्रशासन के माध्यम से संचालित कल्याणकारी व्यवस्था के संपर्क में आने के उपरांत अनीता को निर्माण कामगार मृत्यु सहायता योजना के अंतर्गत त्वरित सहायता उपलब्ध कराई गई। पात्रता के संपूर्ण मानकों पर त्वरित परीक्षण के पश्चात अनीता को मृत्यु सहायता के रूप में सवा दो लाख रुपये की आर्थिक धनराशि प्रदान की गई, जबकि अंत्येष्टि के तात्कालिक संस्कारों के निर्वहन हेतु पच्चीस हजार रुपये की अतिरिक्त राशि भी तत्काल अवमुक्त की गई। कुल ढाई लाख रुपये की इस संयुक्त आर्थिक सहायता ने परिवार को न केवल आर्थिक रूप से टूटने से बचाया, बल्कि उनके सामाजिक मान-सम्मान की भी पूर्ण रक्षा की।

वित्तीय सहायता प्राप्त होने के उपरांत अनीता ने सर्वप्रथम अपनी पुत्री के आगामी वैवाहिक अनुष्ठान की सभी आवश्यक तैयारियां सम्मानपूर्वक पूर्ण कीं। इसके साथ ही, दूरदर्शिता का परिचय देते हुए शेष धनराशि का सदुपयोग स्थानीय स्तर पर पारंपरिक कांच व चूड़ी निर्माण से जुड़े स्वावलंबन कार्य को आरंभ करने में किया। आज वह स्वयं आत्मनिर्भर बनकर अपने परिवार का भरण-पोषण पूर्ण स्वाभिमान के साथ कर रही हैं। किसी भी बिचौलिए अथवा अवांछित हस्तक्षेप के बिना सीधे बैंक खाते में शत-प्रतिशत धनराशि के अंतरण ने शासन की नीति, नीयत और पारदर्शी प्रशासनिक व्यवस्था के प्रति आमजन के विश्वास को दृढ़ किया है। जनपद फिरोजाबाद का यह उदाहरण राज्यव्यापी उस वृहद सुरक्षा तंत्र की एक जीवंत बानगी है, जिसे प्रदेश सरकार ने निर्माण श्रमिकों के लिए संस्थागत रूप दिया है। राज्य में अठारह से साठ वर्ष के आयु वर्ग के वे सभी श्रमिक, जिन्होंने पूर्ववर्ती बारह महीनों की अवधि में न्यूनतम नब्बे दिन निर्माण कार्य किया हो, इस व्यापक कल्याणकारी तंत्र के अंतर्गत विधिवत आच्छादित किए जाते हैं। पंजीयन से लेकर नवीनीकरण तक की संपूर्ण व्यवस्था को सरलीकृत किया गया है, ताकि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े कामगार को अपने वैध अधिकारों की प्राप्ति के लिए किसी जटिल प्रक्रिया से न गुजरना पड़े। निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों का कार्य अत्यंत श्रमसाध्य और जोखिमपूर्ण होता है, जिसमें कार्यस्थल पर दुर्घटना अथवा सामान्य बीमारी से आकस्मिक मृत्यु की आशंका निरंतर बनी रहती है। इस मानवीय पक्ष को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश सरकार द्वारा मृत्यु, विकलांगता सहायता एवं अक्षमता पेंशन का अत्यंत मानवीय एवं संवेदनशील ढांचा तैयार किया गया है। यदि किसी पंजीकृत कामगार की कार्यस्थल पर अथवा कार्य के दौरान दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, तो उसके वैध आश्रितों को पांच लाख रुपये की एकमुश्त आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। वहीं, कार्यस्थल से इतर स्वाभाविक अथवा सामान्य मृत्यु की दशा में दो लाख रुपये का वित्तीय अनुदान देय होता है। अंत्येष्टि के तात्कालिक प्रबंधों के लिए पच्चीस हजार रुपये की अतिरिक्त व्यवस्था प्रत्येक स्थिति में सुनिश्चित की गई है। दुर्घटना के फलस्वरूप यदि कोई श्रमिक स्थायी रूप से पूर्ण अक्षमता का शिकार हो जाता है, तो उसे जीवनयापन के संकट से उबारने के लिए तीन लाख रुपये की एकमुश्त सहायता के साथ-साथ आजीवन मासिक अक्षमता पेंशन का प्राविधान है। आंशिक विकलांगता की स्थिति में शारीरिक क्षति के अनुपात में डेढ़ लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता सीधे प्रदान की जाती है।

योगी सरकार ने 17.33 करोड़ रुपये की दी आर्थिक सहायता, बस हादसों के पीड़ितों व आश्रितों को मिली मदद

यात्रियों के साथ राहगीरों को भी राहत

सहायता

- यात्रियों के साथ राहगीरों को भी राहत, गैर-यात्रियों को भी योजना के साथ जोड़ा गया
- बस हादसे में मौत पर अब 7.50 लाख तक की मदद, घायल यात्रियों के लिए भी मदद का प्रावधान

तमसा संकेत, संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों से होने वाली दुर्घटनाओं में यात्रियों और अन्य प्रभावित लोगों को आर्थिक सहारा देने के लिए संचालित यात्री राहत एवं सुरक्षा योजना पीड़ित परिवारों के लिए बड़ी मदद का माध्यम बनी है। वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2025-26 के बीच मृत्यु और घायल होने के कुल 342 प्रकरणों में 17.33 करोड़ रुपये से अधिक की आर्थिक सहायता दी गई है। योगी सरकार ने यह मदद पीड़ितों और परिवारों को उपलब्ध कराकर उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने के हक की दिशा में गंभीरता से काम किया है। 2017-18 से 2025-26 के बीच मृतकों के परिजनों को दी गई सहायता में लगातार बड़े स्तर पर भुगतान दर्ज है। इस अवधि में सबसे अधिक 2019-20 में 78 मृत्यु प्रकरणों में लगभग 3.68 करोड़ रुपये, 2021-22 में 48 प्रकरणों में लगभग 2.37 करोड़ रुपये की सहायता दी गई। वहीं 2017-18 में 42 प्रकरणों में करीब 2.10 करोड़ रुपये, 2023-24 में 32 प्रकरणों में 1.85 करोड़ रुपये और 2025-26 में 27 प्रकरणों में 1.97 करोड़ रुपये का भुगतान हुआ।

परिवहन निगम (यूपीएसआरटीसी) के वरिष्ठ अधिकारी कहते हैं कि सड़क दुर्घटना में जान गंवाने या घायल होने वाले लोगों के परिवारों को तत्काल आर्थिक राहत उपलब्ध कराने के लिए सरकार व परिवहन निगम की योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। हमारा प्रयास शुरू से यह भी रहा है कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जाए।

गंभीर रूप से घायल यात्रियों को भी राहत

दुर्घटना में घायल होने वाले यात्रियों के लिए भी योजना में राहत का प्रावधान है। सामान्य रूप से घायल होने पर उपचार के लिए 10 हजार रुपये तक और गंभीर रूप से घायल होने पर 25 हजार रुपये तक की अग्रिम राहत संबंधित अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई जा सकती है। वहीं प्रारंभिक राहत के बाद भी घायल यात्री के उपचार पर इससे अधिक खर्च आता है, तो चिकित्सकीय उपचार के प्रमाणित बिलों और संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी की ओर से जारी स्वास्थ्य लाभ प्रमाणपत्र के आधार पर आगे की प्रक्रिया की जाती है।

वयस्क यात्री की मृत्यु पर अब 7.50 लाख रुपये

योजना के नए प्रावधानों में मृत्यु की स्थिति में राहत राशि बढ़ाई गई है। वयस्क यात्री की मृत्यु पर 7.50 लाख रुपये, आधा टिकट लेने वाले बच्चे की मृत्यु पर 3.75 लाख रुपये और परिवहन निगम के नियमों के तहत निःशुल्क यात्रा करने वाले छोटे बच्चे की मृत्यु पर लगभग 1.87 लाख रुपये की राहत राशि निर्धारित है। इससे दुर्घटना में परिवार के कमाने वाले सदस्य की मृत्यु होने पर आश्रित परिवार को तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने में मदद मिलती है।

योजना के तहत 2017 से पहले उपलब्ध दो वर्षों यानी 2015-16 और 2016-17 में मृत्यु के 8 मामलों में 40 लाख रुपये की सहायता दी गई थी। इसके बाद 2017-18 से 2025-26 तक 9 वर्षों में मृत्यु के 322 मामलों में लगभग 17.08 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। वहीं घायल यात्रियों के 20 प्रकरणों में 24.37 लाख रुपये की सहायता दी गई।

पारदर्शी व निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया से कृषि विभाग में युवाओं को मिल रहे रोजगार के व्यापक अवसर

- विगत वर्षों में कृषि विभाग एवं विश्वविद्यालयों के विभिन्न संवर्गों में हजारों पदों पर निष्पक्षता से दी गईं नियुक्तियां
- तकनीक आधारित चयन व मानव संपदा पोर्टल से पारदर्शिता के साथ सुनिश्चित हो रही तैनाती

तमसा संकेत, संवाददाता

लखनऊ। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कृषि विभाग में प्राविधिक सहायक ग्रुप-सी पद पर नवचयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश के कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि प्रदेश सरकार ने कृषि विभाग में युवाओं को पूरी पारदर्शिता, निष्पक्षता और शुचिता के साथ बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए हैं। उन्होंने कहा कि विगत वर्षों में विभाग के विभिन्न संवर्गों में चरणबद्ध तरीके से भर्तियां कर मानव संसाधन को निरंतर मजबूत किया गया है, जिससे विभागीय योजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन और किसानों को आधुनिक तकनीकी सेवाएं उपलब्ध कराना सुनिश्चित हुआ है। कृषि मंत्री ने विगत वर्षों में हुई भर्तियों का ब्यौरा देते हुए बताया कि प्राविधिक सहायक ग्रुप-सी संवर्ग के अंतर्गत वर्ष 2020-21 में 1,817 पदों, वर्ष 2021-22 में 228 पदों तथा वर्तमान 2026 में 3,446 पदों पर पारदर्शी चयन प्रक्रिया के तहत नियुक्तियां प्रदान की गई हैं। इसके अलावा ग्रुप-सी के 2,759 और पदों पर नियुक्ति हेतु मुख्य परीक्षा संपन्न हो चुकी है तथा शेष 815 पदों पर भर्ती के लिए आयोग को शीघ्र अधियाचन भेजा जा रहा है। इसी प्रकार वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप-ए के तहत वर्ष 2021-22 में 456 सीधी नियुक्तियां की गईं, जबकि 148 पदों की मुख्य परीक्षा संपन्न हो चुकी है और पदोन्नति के 366 पदों पर भी कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है।

फास्ट न्यूज

वकीलों के 12 अवैध चैंबर हटेंगे

लखनऊ । लखनऊ जिला न्यायालय के आसपास बने वकीलों के 12 अवैध चैंबरों को हटाने का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने साफ कहा कि वकील या बार एसोसिएशन का पदाधिकारी होने के आधार पर किसी अवैध निर्माण को संरक्षण नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि न्यायालय परिसर और सार्वजनिक रास्ते अतिक्रमण से मुक्त होने चाहिए।

जेपीएनआईसी 30 साल की लीज पर, 2 कंपनियां मिलकर चलाएंगी

लखनऊ। गोमती नगर स्थित जय प्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर (JPNIC) को 2 निजी कंपनियां मिलकर चलाएंगी। प्रदेश सरकार ने वृंदावन बॉटलर्स प्राइवेट लिमिटेड और रॉकवुड होटल एंड रिसॉर्ट प्राइवेट लिमिटेड को 30 साल की लीज पर देने की मंजूरी दी है। दोनों कंपनियों की जिम्मेदारी सेंटर का संचालन, मरम्मत, रखरखाव और उसे दोबारा व्यवस्थित करके शुरू करना होगा। इन्हीं शर्तों के साथ लीज समझौता किया जाएगा। करीब 20 एकड़ क्षेत्र में बने JPNIC का निर्माण समाजवादी पार्टी सरकार के दौरान वर्ष 2013 में शुरू हुआ था।

सपाइयों ने राहगीरों को बांटी पीडीए चीनी

लखनऊ । लखनऊ में मंगलवार को समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चीनी के बढ़ते दामों के विरोध में प्रदर्शन किया। सपा कार्यकर्ता 1-1 किलो चीनी के पैकेट लेकर बापू भवन से विधानसभा के बीच पहुंचे और राहगीरों को मुफ्त में चीनी बांटी। इस दौरान उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की।

खबर का हुआ असर, धंसे गहरे गड्ढे को गिट्टी डालकर भरवाया गया

तमसा संकेत, संवाददाता

सूरतगंज (बाराबंकी)। सूरतगंज-हेतमापुर मार्ग पर सड़क किनारे धंसे गहरे गड्ढे को गिट्टी डालकर भर दिया गया है। हिन्दी दैनिक तमसा संकेत समाचार द्वारा इस समस्या को प्रमुखता से उठाए जाने के बाद संबंधित विभाग ने कार्रवाई की, जिससे मार्ग से गुजरने वाले ग्रामीणों और वाहन चालकों को तत्काल राहत मिली है।

यह गड्ढा शुक्रवार देर रात हुई तेज बारिश के बाद बना था। बंभनावा पुल से लगभग 50 मीटर आगे हेतमापुर की ओर जाने वाले मार्ग के हाल ही में चौड़े किए गए हिस्से का किनारा धंस गया था। इसके परिणामस्वरूप सड़क किनारे करीब दो फीट लंबा और लगभग चार फीट गहरा गड्ढा बन गया था।। इस गहरे गड्ढे के कारण बाइक सवारों और छोटे वाहनों के लिए दुर्घटना का खतरा बना हुआ था। शनिवार को ग्रामीणों ने गड्ढा देखकर इसकी जानकारी आसपास के लोगों को दी थी। ग्रामीणों ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए कहा था कि चौड़ीकरण का कार्य अभी पूरा भी नहीं हुआ है और नया हिस्सा धंसने लगा है। हिन्दी दैनिक तमसा संकेत समाचार पत्र ने इस मामले को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। खबर प्रकाशित होने के बाद संबंधित विभाग ने संज्ञान लिया और सोमवार शाम धंसे हिस्से में गिट्टी डालकर गड्ढे को भर दिया गया। क्षेत्रीय निवासी अमित सिंह राठौर, सत्यवान वर्मा, राजेश तिवारी, त्रिभवन, सूरज, रोहित और दीपक सहित अन्य ग्रामीणों ने इस कार्रवाई पर संतोष व्यक्त किया है। हालांकि, ग्रामीणों ने केवल गिट्टी डालकर खानापूर्ति न करने की मांग की है।

बिना इलाज बिल लगाने और गलत लाभार्थी पर कार्रवाई, अनावश्यक इलाज और गुणवत्ता मानकों में कमी पर भी कार्रवाई

योगी सरकार आयुष्मान योजना में दिशानिर्देशों को लेकर सख्त

- अवैध वसूली, फर्जी बिलिंग और नियम तोड़ने पर भारी जुर्माना, पहली-दूसरी और तीसरी गलती पर अलग-अलग दंड का प्रावधान

तमसा संकेत, संवाददाता

लखनऊ। योगी सरकार ने आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से जुड़े सभी अस्पतालों को योजना के नियमों और आपत्तिजनक कार्यप्रणाली विरोधी दिशानिर्देशों का पालन अनिवार्य रूप से करने के सख्त निर्देश दिये हैं ताकि लाभार्थियों को बेहतर और पारदर्शी इलाज मिले। ऐसे में सीएम योगी के निर्देश पर स्टेट हेल्थ एजेंसी (साचीज) अस्पतालों को लगातार इन नियमों की जानकारी दे रही है। डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने बताया कि इसके बाद भी नियमों का उल्लंघ करने, लाभार्थी से अवैध वसूली, बिना इलाज के बिल लगाना, गलत लाभार्थी के नाम पर इलाज दर्ज करना, अनावश्यक इलाज या तय मानकों का पालन नहीं करने पर अस्पतालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

पहली बार उल्लंघन पर अतिरिक्त क्लेम राशि के दस गुना तक तथा दूसरी बार उल्लंघन पर बीस गुना तक दंड एवं निलंबन की कार्रवाई की जा सकती है। तीसरी बार उल्लंघन पर डी-एम्पैनलमेंट/ब्लैकलिस्टिंग का प्रावधान है।

पहली बार उल्लंघन पर पांच गुना तक तथा दूसरी बार उल्लंघन पर दस गुना तक दंड एवं निलंबन की कार्रवाई हो सकती है। तीसरी बार उल्लंघन पर डी-एम्पैनलमेंट/ब्लैकलिस्टिंग की कार्रवाई की जा सकती है।

नियम तोड़ने पर पहली, दूसरी और तीसरी बार अलग कार्रवाई

लाभार्थी से अवैध नकद भुगतान: पहली बार नियम तोड़ने पर राशि का पूर्ण रिफंड तथा अवैध भुगतान की राशि का पांच गुना दंड, दोबारा उल्लंघन पर क्लेम निरस्तीकरण एवं चिकित्सालय का निलंबन तथा तीसरी बार उल्लंघन पर डी-एम्पैनलमेंट/ब्लैकलिस्टिंग की कार्रवाई की जा सकती है।

बिना सेवा दिए बिलिंग: पहली बार उल्लंघन पर क्लेम निरस्त करने के साथ क्लेम राशि के पांच गुना तक दंड, दूसरी बार उल्लंघन पर दस गुना तक दंड एवं निलंबन तथा तीसरी बार उल्लंघन पर डी-एम्पैनलमेंट/ब्लैकलिस्टिंग का प्रावधान है।

साचीज की वेबसाइट पर देखें दिशानिर्देश

डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर आयुष्मान योजना से जुड़े अस्पतालों को आपत्तिजनक कार्यप्रणाली विरोधी दिशानिर्देशों की जानकारी दी जा रही है। योगी सरकार का प्रयास है कि अस्पताल पहले से ही नियमों को समझें और अपने स्तर पर कमियों को दूर करें, ताकि मरीजों को परेशानी न हो और योजना में किसी तरह की गड़बड़ी न हो। उन्होंने बताया कि सभी सूचीबद्ध अस्पताल आपत्तिजनक कार्यप्रणाली संबंधी दिशानिर्देश साचीज की आधिकारिक वेबसाइट https://sachis.in/ पर देख और डाउनलोड कर सकते हैं। विभाग की ओर से अस्पतालों को सलाह दी जा रही है कि वे अपने डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ, बिलिंग कर्मचारियों और प्रशासनिक कर्मचारियों को भी इन नियमों की जानकारी दें।

केन्या, ब्राजील, अर्जेंटीना, दक्षिण अफ्रीका और सेनेगल के करीब 70 वरिष्ठ अधिकारियों एवं प्रतिनिधियों ने किया विद्यालयों का दौरा

योगी सरकार के निपुण मॉडल को समझने गाजियाबाद पहुंचे पांच देशों के प्रतिनिधि

- योगी सरकार के निपुण मॉडल को समझने गाजियाबाद पहुंचे पांच देशों के प्रतिनिधि
- विद्यार्थियों, शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों, एआरपी और राज्य संसाधन समूह के अधिकारियों से किया संवाद
- पाठ्यक्रम, संरचित शिक्षण सामग्री, शिक्षक मेंटरिंग, आकलन और आंकड़ों के उपयोग पर हुई तकनीकी चर्चा

तमसा संकेत, संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बुनियादी शिक्षा और बच्चों की सीखने की क्षमता को मजबूत करने के प्रयास अब अंतरराष्ट्रीय पीयर-लर्निंग का विषय बन रहे हैं। निपुण भारत मिशन के अंतर्गत भारत में बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान (एफएलएन) सुधारों को समझने के उद्देश्य से केन्या, ब्राजील, अर्जेंटीना, दक्षिण अफ्रीका और सेनेगल के वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों एवं नागरिक समाज के प्रतिनिधियों का लगभग 70 सदस्यीय दल गाजियाबाद पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल ने परिषदीय विद्यालयों में कक्षा शिक्षण का प्रत्यक्ष अवलोकन कर निपुण भारत की नीतियों के जमीनी क्रियान्वयन को समझा। 23 से 27 अगस्त तक चल रहे सप्ताहभर के पीयर-लर्निंग इमर्शन कार्यक्रम के अंतर्गत प्रतिनिधिमंडल को छोटे-छोटे समूहों में विभाजित कर गाजियाबाद के नगर, राजापुर, लोनी और मुरादनगर ब्लॉकों के 11 विद्यालयों का भ्रमण कराया गया। प्रतिनिधियों ने कक्षा-कक्ष में शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया देखी तथा विद्यार्थियों, शिक्षकों, प्रधानाचार्यों, अकादमिक रिसोर्स पर्सन्स (एआरपी) और राज्य संसाधन समूह के अधिकारियों से संवाद किया। गाजियाबाद के परिषदीय विद्यालयों में पांच देशों के प्रतिनिधियों का यह अध्ययन दौरा उत्तर प्रदेश में निपुण भारत मिशन के अंतर्गत एफएलएन सुधारों को नीति से कक्षा तक पहुंचाने की प्रक्रिया को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर साझा सीख का अवसर प्रदान कर रहा है। कार्यक्रम का उद्देश्य भारत में निपुण भारत मिशन के अंतर्गत एफएलएन सुधारों को समझना और अनुभव साझा करना है। गाजियाबाद के विद्यालयों में कक्षा शिक्षण के प्रत्यक्ष अवलोकन और शिक्षा अधिकारियों के साथ तकनीकी संवाद के माध्यम से प्रतिनिधियों ने एफएलएन सुधारों के जमीनी क्रियान्वयन को करीब से समझा।

11 परिषदीय विद्यालयों में देखा कक्षा शिक्षण

23 से 27 अगस्त तक चल रहे पीयर-लर्निंग इमर्शन कार्यक्रम के अंतर्गत समझे निपुण भारत मिशन के एफएलएन सुधार

नगर, राजापुर, लोनी और मुरादनगर ब्लॉकों के 11 विद्यालयों में कक्षा शिक्षण का किया प्रत्यक्ष अवलोकन

शिक्षा विभाग के साथ हुई तकनीकी चर्चा

विद्यालयों के दौरे के बाद उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग के साथ विस्तृत तकनीकी चर्चा हुई। इसमें गाजियाबाद के जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी और राज्य संसाधन समूह के सदस्य शामिल हुए। चर्चा में पाठ्यक्रम एवं अध्ययन उद्देश्यों, संरचित शिक्षण-अधिगम सामग्री, शिक्षक मार्गदर्शन एवं मेंटरिंग, आकलन और आंकड़ों के उपयोग पर विचार-विमर्श हुआ। साथ ही सुधारों को बड़े स्तर पर लागू करने में मिडिल टीयर की भूमिका पर भी चर्चा की गई।

यू पी आई ने भारत की डिजिटल शक्ति को वैश्विक पहचान दिलाई

- डिजिटल भुगतान को सरल, सुरक्षित एवं पारदर्शी बनाकर यू पीआई ने वित्तीय समावेशन को दी नई गति : केशव प्रसाद

तमसा संकेत, संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) के 10 गौरवपूर्ण वर्ष पूर्ण होने पर समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के कुशल एवं दूरदर्शी नेतृत्व में यूपीआई ने भारत में डिजिटल भुगतान की व्यवस्था को सरल, सुरक्षित, त्वरित और पारदर्शी बनाकर सुशासन एवं वित्तीय समावेशन को नई गति प्रदान की है। यूपीआई ने डिजिटल लेन-देन को आम नागरिक के जीवन का सहज हिस्सा बनाते हुए देश की अर्थव्यवस्था को नई मजबूती प्रदान की है। उन्होंने कहा कि डिजिटल क्रांति ने बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाओं को जन-जन की पहुंच तक पहुंचाने का कार्य किया है। आज रेहड़ी-पटरी लगाने वाले छोटे दुकानदारों, किसानों और श्रमिकों से लेकर छोटे-बड़े व्यापारियों तथा उद्यमियों तक, समाज के प्रत्येक वर्ग को यूपीआई के माध्यम से सुगम और त्वरित भुगतान की सुविधा मिल रही है। इससे आर्थिक गतिविधियों को गति मिली है और आमजन के सशक्तीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ है। मौर्य ने कहा कि एक अभिनव पहल के रूप में शुरू हुआ यूपीआई आज आत्मनिर्भर भारत की डिजिटल शक्ति और वैश्विक पटल पर भारत की तकनीकी क्षमता का सशक्त प्रतीक बन चुका है।

चर्चा: अपने छात्र जीवन की यादें साझा कर युवाओं को दी लोकतंत्र में सक्रिय भागीदारी की सीख

ज्ञानेश कुमार गुप्ता ने छात्रों से किया प्रेरक संवाद

तमसा संकेत, संवाददाता

लखनऊ । भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार ने अपने दो दिवसीय लखनऊ दौरे के दौरान ऐतिहासिक कॉल्विन तालुकेदार्स कॉलेज के अवध हॉल में छात्रों के साथ प्रेरणादायक संवाद किया। इस दौरान उन्होंने अपने छात्र जीवन की स्मृतियों को साझा करने के साथ ही भारतीय लोकतंत्र, चुनावी प्रक्रिया, ईवीएम की विश्वसनीयता, फेक न्यूज से सतर्कता और युवा मतदाताओं की भूमिका पर विस्तार से चर्चा की। ज्ञानेश कुमार ने बताया कि अमेरिका जाने की तैयारी के दौरान उनकी माताजी की इच्छा और मातृभूमि के प्रति लगाव ने उन्हें देश में रहकर जनसेवा करने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद उन्होंने आईएएस की परीक्षा उत्तीर्ण की और केरल कैडर से प्रशासनिक सेवा की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि देश सेवा की इसी यात्रा ने उन्हें आज विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के दायित्व तक पहुंचाया है। भारतीय चुनाव व्यवस्था की विशालता का उल्लेख करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि भारत में करीब 100 करोड़ मतदाता हैं और इतनी बड़ी आबादी के लिए चुनाव कराना अपने आप में एक विशाल कार्य है। उन्होंने बताया कि निर्वाचन प्रक्रिया को सुचारु रूप से संपन्न कराने में बड़ी संख्या में अधिकारी और कर्मचारी जिम्मेदारी निभाते हैं। भारत निर्वाचन आयोग संविधान, कानून और निर्धारित दिशा-निर्देशों के तहत स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है।मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने युवाओं से लोकतंत्र में सक्रिय भागीदारी का आह्वान करते हुए संविधान के अनुच्छेद 326 का उल्लेख किया। उन्होंने 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले विद्यार्थियों से अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने की अपील की।

पढ़ाई के साथ-साथ खेलकूद में भी उनकी विशेष रुचि रही

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने वर्ष 1979 के अपने छात्र जीवन, अपने शिक्षकों और विद्यालय से जुड़ी स्मृतियों को साझा करते हुए कहा कि आज वे जिस मुकाम पर हैं, उसमें विद्यालय और उनके गुरुओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने बताया कि पढ़ाई के साथ-साथ खेलकूद में भी उनकी विशेष रुचि रही। उन्होंने छात्रों से कहा कि शिक्षा और खेलकूद जीवन में समान रूप से महत्वपूर्ण हैं तथा विद्यार्थियों को दोनों क्षेत्रों में संतुलन बनाकर आगे बढ़ना चाहिए।

- ईवीएम से संबंधित सवालों पर उन्होंने स्पष्ट किया कि भारतीय ईवीएम सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों द्वारा निर्मित की जाती हैं और वे इंटरनेट, ब्लूटूथ या वाई-फाई से जुड़ी नहीं होतीं। उन्होंने छात्रों को सोशल मीडिया के दौर में भ्रामक सूचनाओं और फेक न्यूज से सावधान रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि किसी भी सूचना को स्वीकार करने से पहले उसके स्रोत और सत्यता की जांच करना आवश्यक है।

योगी सरकार की योजनाओं से आत्मनिर्भर बनीं उषा देवी

उषा देवी ने किराने की दुकान से बदली अपनी जिंदगी, 130 महिलाओं को भी दिखाई राह

- जुलाई 2022 में मिला 1.50 लाख रुपये का ऋण, छोटे व्यवसाय से मजबूत हुई परिवार की आर्थिक स्थिति
- पड़ोसी गांव की महिलाओं से मिली प्रेरणा, स्वयं सहायता समूह से जुड़कर शुरू किया बदलाव का सफर
- बकरी पालन, गाय पालन, मुर्गी पालन और छोटे व्यवसायों के जरिए गांव की महिलाएं बन रहीं आत्मनिर्भर

तमसा संकेत, संवाददाता

लखनऊ/गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त करने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से हजारों महिलाएं आज स्वरोजगार से जुड़कर अपने परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत कर रही हैं। गोरखपुर के चरगांवा ब्लॉक के नाहरपुर गांव की रहने वाली उषा देवी की कहानी भी इसी बदलाव की प्रेरक मिसाल है, जिन्होंने स्वयं सहायता समूह से जुड़कर न केवल अपनी जिंदगी बदली, बल्कि गांव की सैकड़ों महिलाओं के लिए प्रेरणा बन गईं। उषा देवी बताती हैं कि करीब चार वर्ष पहले उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी। घर के खर्चों को पूरा करने में कठिनाई होती थी और आय का कोई स्थायी साधन नहीं था। इसी दौरान उन्हें पड़ोसी गांव की महिलाओं से स्वयं सहायता समूह के बारे में जानकारी मिली। उन महिलाओं ने उषा देवी को समूह से जुड़ने और अन्य महिलाओं को भी इससे जोड़ने के लिए प्रेरित किया। उषा देवी ने इस अवसर को अपने जीवन में बदलाव लाने का माध्यम बनाया और स्वयं सहायता समूह से जुड़ गईं।

बोलीं- जिसके साथ जीना-मरना, उसके लिए किडनी कुछ भी नहीं, ससुर बोले- बहू 'सावित्री' बनी

आगरा में टीचर पति को पत्नी ने दी किडनी

प्रशंसा

तमसा संकेत, एजेंसी

आगरा। आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में पहली बार किडनी ट्रांसप्लांट हुआ। पहला ट्रांसप्लांट टीचर महेंद्र कुशवाहा का हुआ। उनकी पत्नी मीना ने अपनी एक किडनी देकर पति को नया जीवन दिया है। अब महेंद्र और मीना दोनों स्वस्थ हैं और डॉक्टरों की निगरानी में हैं।

सोमवार को मीना ने पति से वीडियो कॉल पर बात की। कहा- आप ठीक तो हैं? मीना ने कहा कि मैंने जिसके साथ जीने-मरने की कसम खाई, उसके लिए एक किडनी कुछ भी नहीं है। मैं बहुत खुश हूं कि मेरी किडनी पति के काम आई। इतना कहते ही मीना की आंखें छलक पड़ीं।

मीना ने कहा कि पति की लंबी उम्र के लिए कुछ भी कर सकती हूं।

2 मिनट तक पति से बात करने के बाद मीना को तसल्ली हुई। उन्होंने भगवान और डॉक्टरों का शुक्रिया अदा किया। हाथरस के सिकंदराराऊ में रहने वाले महेंद्र कुशवाहा (32) एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। डेढ़ साल पहले उन्हें पता चला कि उनकी किडनी खराब हैं। इसके बाद से वह लगातार डायलिसिस करा रहे थे। शरीर कमजोर होता जा रहा था। डायलिसिस के लिए पत्नी मीना खुद उन्हें लेकर एसएन मेडिकल कॉलेज आती थीं। मीना 3 बच्चों की परवरिश के साथ घर भी संभालती रहीं। डॉक्टर ने मीना को बताया कि किडनी ट्रांसप्लांट होने पर महेंद्र की जान बच सकती है। प्राइवेट अस्पतालों में खर्च अधिक होने से ट्रांसप्लांट के लिए रुपए का इंतजाम महेंद्र और मीना के लिए चुनौती बन गया। इसी बीच उन्हें एसएन मेडिकल कॉलेज में किडनी ट्रांसप्लांट की सेवाएं शुरू होने के बारे में पता चला। इसके बाद मीना ने पति को दिखाकर रजिस्ट्रेशन कराया और अपनी किडनी देने का फैसला किया।

ट्रांसप्लांट के 3 बाद पति-पत्नी में वीडियो कॉल पर हुई बात

जांच में मीना की रिपोर्ट भी ठीक आई। इसके बाद 22 अगस्त को एसएन मेडिकल कॉलेज में महेंद्र का किडनी ट्रांसप्लांट किया गया। यह मेडिकल कॉलेज के इतिहास में पहला मौका था, जब ये सर्जरी हुई। इसके बाद से मीना और महेंद्र एसएन के आइसोलेट वार्ड में भर्ती हैं। सोमवार को डॉक्टरों ने पति-पत्नी की फोन पर वीडियो कॉल कर बात कराई। इसमें एक-दूसरे का हाल जाना।

> **मीना ने बताया- जब मुझे पता चला कि पति की दोनों किडनियां खराब हैं। अब केवल ट्रांसप्लांट ही एक रास्ता है। ऐसे में किडनी दान करने का बात आई। इसक पर मैंने एक मिनट में ही पति को किडनी देने का फैसला कर लिया।**

महेंद्र ने भी वीडियो कॉल पर पत्नी का हालचाल लिया। पति का चोहरा देखकर मीना रोने लगीं।

ससुर बोले- बेटे के लिए बहू सावित्री बन गई

महेंद्र के पिता पप्पू सिंह ने भी बेटे से बात की। उन्होंने बताया कि बेटे की हालत ठीक है। पप्पू सिंह बहू मीना को उनके इस त्याग के लिए आशीर्वाद दे रहे। उनका कहना है कि बहू बेटे के लिए सावित्री बनकर आई है। हमारे लिए वह किसी देवी से कम नहीं है।

बांके बिहारी मंदिर में चढ़ावा चोरी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त

तमसा संकेत, एजेंसी

कहा- श्रद्धालुओं का एक-एक पैसा दानपेटी में डालें या ट्रेजरी में जमा करें

मथुरा । वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में आने वाले दान को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बड़ा निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा- मंदिर में दान किया गया एक-एक पैसा पहले दानपेटी में डाला जाए। या फिर दान की रकम मंदिर के आधिकारिक ऑनलाइन तरीके से सीधे मंदिर के खाते में जानी चाहिए। चढ़ावे की चोरी नहीं होने देंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मंदिर से जुड़े सेवायत, पुजारी या कोई और व्यक्ति दान की रकम अपने पास नहीं रख सकता। कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि श्रद्धालु की ओर दिया गया दान भगवान के लिए है। उस पर सबसे पहला अधिकार भगवान का है। मंदिर के खजाने में जमा होने के बाद ही सेवायतों या संबंधित लोगों को उनका हिस्सा मिल सकता है।

दरअसल, मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ के सामने एक वीडियो पेश किया गया था। इसमें 3 लोग मंदिर की दानपेटी के सामने खड़े दिखाई दे रहे हैं। श्रद्धालुओं से पैसे लेकर उन्हें पॉलीथिन की थैलियों में जमा कर रहे हैं। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और वी. मोहना की बेंच ने वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश दिया।

फास्ट न्यूज

जेई के ट्रेन से कटकर हुए अलग दोनों पैर, मौत

आगरा। आगरा-झांसी रेलवे ट्रैक पर रेलवे विभाग के अवर अभियंता ट्रेन की चपेट में आ गए। हादसे में उनके दोनों पैर धड़ से अलग हो गए और वह गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद वह बेहोश नहीं हुए लोगों को एक टक देखते रहे। रेलवे कर्मचारियों की सूचना पर पुलिस और एंबुलेंस मौके पर पहुंची। सीएचसी सैंया में प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें एसएन अस्पताल आगरा रेफर किया गया, जहां शाम करीब 7 बजे इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।

कानपुर में एक्सपायरी चॉकलेट कार वाले लूट ले गए

कानपुर। कानपुर में कूड़े के ढेर में पड़ी एक्सपायरी चॉकलेटों और टॉफियों को लूटने की होड़ मच गई। बाइक और कार सवार लोग सड़क किनारे गाड़ियां खड़ी कर चॉकलेट-टॉफी बटोरने में जुट गए। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस और खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम मामले की जांच में जुट गई है।

वीडियो में दिख रहा कि कूड़े के ढेर में टॉफियों और चॉकलेटों के बॉक्स पड़े हैं। कुछ लोग बोरियों में चॉकलेट के डिब्बे भर रहे हैं। देखते ही देखते लोगों की भीड़ जमा हो जाती है।

पनकी की गौशाला का निरीक्षण

कानपुर। भारतीय गौ रक्षा संघ के पदाधिकारियों ने पनकी स्थित गौशालाओं का निरीक्षण किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चन्द्रानंद गिरी महाराज के निर्देशन पर राष्ट्रीय संगठन मंत्री सौरभ बाजपेयी, महामंत्री मुन्ना हजारिया, संयोजक जगमोहन सिंह, कानपुर प्रभारी गोरे लाल और जिला अध्यक्ष भरत पाण्डेय सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने पनकी स्थित नंदी गौशाला और हनुमान गौशाला का निरीक्षण किया।

अग्रवंश समाज ने धूमधाम से मनाया हरियाली तीज महोत्सव

तमसा संकेत, संवाददाता

लखनऊ। अग्रवंश समाज की ओर से दयालबाग, सुशांत गोल्फ सिटी में हरियाली तीज पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ मनाया गया। शुभारंभ महाराजा श्री अग्रसेन जी की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम में समाज की महिलाओं और पुरुषों ने हिस्सा लिया। अध्यक्षता केके अग्रवाल ने की। इस दौरान श्री अग्रवंश समाज के संरक्षक कुलदीप गुप्ता, नमन सरावगी, अजय अग्रवाल, अनीश गर्ग, रचना मित्तल सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। महोत्सव का इसके बाद पारंपरिक गीतों एवं नृत्य की मनमोहक प्रस्तुतियों ने सभी का मन मोह लिया। महिलाओं ने विशेष रूप से राजस्थानी नृत्य प्रस्तुत कर कार्यक्रम में लोक संस्कृति और परंपरा के रंग भर दिए। इस दौरान मनोरंजक खेल प्रतियोगिताओं का भी आयोजन हुआ। महिलाओं एवं अन्य सदस्यों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान आपसी मेल-जोल, सौहार्द और सामाजिक एकता का संदेश भी देखने को मिला। स्वादिष्ट व्यंजनों के भोज के साथ हरियाली तीज महोत्सव का समापन हुआ।

तेंदुए ने सिपाही की मां को मार डाला

खेत पर निराई करते वक्त गर्दन पकड़ा, साथ काम कर रहीं महिलाओं ने दरातीं फेंककर भगाया

तमसा संकेत, एजेंसी

सुरजनगर (ठाकुरद्वारा), मुरादाबाद। मुरादाबाद में एक तेंदुए के हमले में यूपी पुलिस के सिपाही की मां की मौत हो गई। वह खेत पर धान की गांव की महिलाओं के साथ निराई कर रही थीं। खेत पर पहले से घात लगाए तेंदुए ने अचानक उनकी गर्दन पर हमला कर दिया। गर्दन पर गहरे घाव होने के कारण उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। खेत पर साथ में काम कर रही एक एक महिला ने दरांती फेंककर तेंदुए को भगाया। इस दौरान एक अन्य महिला भी बेहोश होकर गिर पड़ी। सूचना मिलते ही मौके पर थाना प्रभारी, सीओ और वन अधिकारी पहुंच गए। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों को शांत कराया। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है।

मौके पर भाजपा कार्यकर्ता ठाकुर अजय प्रताप और ब्लॉक प्रमुख वीर सिंह सैनी भी पहुंचे। ग्रामीणों ने वन विभाग से क्षेत्र में पिंजरा लगाकर तेंदुए को जल्द पकड़ने और पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग की है। मामला जिला मुख्यालय 20 किलोमीटर दूर ठाकुरद्वारा थाना क्षेत्र के बहापुर बलिया गांव की है। बहापुर बलिया निवासी मिथिलेश देवी (45) पत्नी बृजपाल उर्फ गुड्डू मंगलवार सुबह करीब 10.45 बजे गांव की अन्य महिलाओं के साथ खेत पर धान की निराई करने गई थीं। खेत से डेढ किलोमीटर दूरी पर जंगल स्थित है।

एक हफ्ते में यह दूसरी घटना

18 अगस्त सुबह करीब 11 बजे बहापुर बलिया निवासी बिरमो देवी (60) पत्नी बलराम सिंह की मौत तेंदुए के हमले में हो गया था। वह खेत पर चारा लेने के लिए गई थी, इसी दौरान तेंदुए ने उनकी गर्दन पर अटैक कर दिया था। इससे मौके पर ही उन्होंने दम तोड़ दिया था।

> डीएफओ डॉ विनय कुमार ने बताया-बहापुर बलिया गांन की घटना अत्यंत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। इस क्षेत्र को अति-संवेदनशील घोषित कर दिया है। तेंदुए को पकड़ने के लिए क्षेत्र में आधुनिक थर्मल ड्रोन से 24 घंटे निगरानी की जा रही है। आबादी के रास्तों पर अतिरिक्त सक्रिय पिंजरे लगाए जा रहे हैं। वन विभाग की विशेष रेस्क्यू टीम और ट्रैंकुलाइजर एक्सपर्ट्स को इलाके में उतार दिया गया है। तेंदुए को जल्द से जल्द सुरक्षित पकड़ लिया जाएगा।

घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर सैकड़ों ग्रामीण इकट्टा हो गए

घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर सैकड़ों ग्रामीण इकट्ठा हो गए। पुलिस और वन अधिकारियों को तत्काल इसकी सूचना दी गई। मौके पर थाना प्रभारी मनोज प्रमार, सीओ आशीष प्रताप सिंह और एसडीएम वेद प्रकाश पांडेय मौके पर पुलिस फोर्स के साथ पहुंच गए। डीएफओ डॉक्टर विनय कुमार भी वनकर्मियों के साथ तेंदुए की तलाश में जुट गए।

6.00 हे0 ग्रामसभा की भूमि पर्यटन विभाग के पक्ष में निःशुल्क हस्तान्तरित किये जाने का प्रस्ताव

दुर्लभ पक्षियों के संरक्षण के साथ ही पर्यटकों के लिए बढ़ेगी सुविधाए

तमसा संकेत, संवाददाता

लखनऊ। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में आज सम्पन्न हुई कैबिनेट बैठक में जनपद मैनपुरी में समान पक्षी विहार के निकट पर्यटन विकास हेतु 6.00 हे0 ग्रामसभा की भूमि पर्यटन विभाग के पक्ष में निःशुल्क हस्तान्तरित करने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

यह जानकारी प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री जयवीर सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि यह भूमि मैनपुरी की किसनी तहसील के समान पक्षी विहार के निकट ग्राम समान में स्थित है और ग्राम समाज की यह भूमि ऊसर है। यह भूमि पक्षी वन्यजीव विहार के निर्माण हेतु जिलाधिकारी मैनपुरी ने प्रस्तावित किया था। समान पक्षी वन्यजीवन

विहार के पर्यटन विकास को बढ़ावा देने के लिए भी प्रस्ताव पारित किया गया था।

उन्होंने बताया कि मैनपुरी का समान पक्षी विहार प्रदेश का एक महत्वपूर्ण वेटलैंड है और रामसर साइट है, जो सारस, क्रेन और कई तरह के प्रवासी पक्षियों का घर है। खासकर गंगा के मैदानी इलाकों में स्थित एक मौसमी झील के पास स्थित है, जो पक्षी प्रेमियों के लिए एक शानदार स्थान है। समान ग्राम स्थित इसे 2019 संरक्षित रामसर स्थल घोषित किया गया है। यह स्थान आगरा-मैनपुरी-फर्रूखाबाद मार्ग पर समान गॉव में स्थित है। यह मैनपुरी शहर से लगभग 30 किमी0 दूर और आगरा-अलीगढ़ सड़क मार्ग से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। इस स्थान पर रेलमार्ग द्वारा भी पहुंचा जा सकता है।

इन पक्षी विहारों में बड़ी संख्या में देश और विदेशों से भी पक्षियों की विभिन्न प्रजातियॉ खासतौर से शरद ऋतु में आगमन होता है। उन्होंने बताया कि पर्यटन विभाग भूमि हस्तान्तरित हो जाने से समान पक्षी विहार के निकट पर्यटकों को पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए समुचित भूमि उपलब्ध हो जायेगी और पक्षियों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए भी आवश्यक व्यवस्थाएं की जा सकेगी।

क्रेन पक्षी को देखने के लिए राज्य के सबसे उपयुक्त स्थलों में से एक

पर्यटन मंत्री ने बताया कि समान ग्राम स्थित संरक्षित रामसर साइट्स 5.25 वर्ग किमी0 क्षेत्रफल में फैला हुआ है। क्रेन पक्षी को देखने के लिए राज्य के सबसे उपयुक्त स्थलों में से एक है। साथ ही अभ्यारण पक्षी दर्शन और फोटोग्राफी के लिए एक आदर्श स्थान भी है। यहां नाव सवारी करके पक्षियों को करीब से देखा जा सकता है। वैसे उ0प्र0 में कई पक्षी विहार हैं। जैसे चन्द्रशेखर पक्षी विहार कन्नौज, सैंडी पक्षी विहार हरदोई, बखीरा पक्षी विहार संतक-बीरनगर, विजय सागर पक्षी विहार महोबा, लाखबहोसी पक्षी विहार उन्नाव, डा0 भीमराव अम्बेडकर पक्षी विहार प्रतापगढ़, सुरहाताल पक्षी विहार बलिया, ओखला पक्षी विहार गौतमबुद्ध नगर, सूरसरोवर पक्षी विहार आगरा, समान पक्षी विहार मैनपुरी तथा पटन पक्षी विहार एटा शामिल हैं।

मुरादाबाद में तेंदुए के हमले में एक और मौत

ठाकुरद्वारा में महिला को मार डाला हमले में 20 दिन में 3 की जान गई, 20 घायल

तमसा संकेत, एजेंसी

मुरादाबाद । मुरादाबाद में तेंदुए के हमले में मंगलवार को एक और महिला की मौत हो गई। तेंदुए ने हमला करके एक महिला को मार डाला। इसके साथ ही पिछले 21 दिन में तेंदुए के हमलों में मरने वालों की संख्या 3 हो गई है। जबकि 20 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं।

ताजा घटना मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा थाना क्षेत्र में बलिया गांव की है। यहां एक महिला पर हमला करके तेंदुए ने उसे मार डाला।

घटना के बाद से ग्रामीणों में गुस्सा है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन और वन विभाग लगातार हो रही घटनाओं को रोकने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहा है।

पिछले 20 दिनों में जिले में तेंदुओं के हमलों में 2 महिलाओं की मौत हो चुकी है। वहीं 20 से ज्यादा किसान घायल हुए हैं। सबसे ज्यादा असर ठाकुरद्वारा और डिलारी क्षेत्र के करीब 50 गांवों में है। अब तेंदुओं का दायरा दूसरे इलाकों में भी बढ़ता नजर आ रहा है।

मंगलवार को ही ठाकुरद्वारा के सहसपुरी गांव में वन विभाग द्वारा लगाए गए पिंजड़े में एक तेंदुआ कैद हुआ है। इसके साथ ही पकड़े गए तेंदुओं की संख्या एक शावक समेत 10 हो गई है। लेकिन इसके बाद भी तेंदुओं के हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं।

इससे साफ है कि तेंदुए बड़ी तादाद में जिले के जंगलों में भटक रहे हैं। वन विभाग के 50 कर्मचारियों की एक टीम तेंदुओं को रेस्क्यू करने के टास्क पर लगाई गई है। लेकिन लगातार होते हमलों की वजह से लोगों में प्रशासन के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है।

पृष्ठ 01 का शेष...

छह महीने में देंगे ...

पहले फरवरी से शुरू हुई परीक्षा जून में लू-तपती गर्मी तक चलती थी। अब नकलविहीन परीक्षा और समय से परिणाम आ रहे हैं। विश्वविद्यालयों को भी सुधार लाने का निर्देश दिया गया है। शिक्षण संस्थान बच्चों की स्किलिंग, करियर, रोजगार के लिए भी खुद को तैयार करें।

सीएम ने कहा कि इन 9.30 लाख युवाओं ने डेमोग्राफिक डिविडेंड के रूप में यूपी को लाभान्वित किया है। यूपी की अर्थव्यवस्था व प्रतिव्यक्ति आय को तीन गुना करने में योगदान दिया है। पिछली सरकारें युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करती थीं। बंदरबांट कर पैसे के बल पर नौकरी देती थीं, लेकिन आज युवाओं के चेहरे की खुशी बता रही है कि बिना किसी लेनदेन, सिफारिश के उनके सपनों को उड़ान मिल रही है। युवा यूपी को बीमारू राज्य से उबारकर टॉप-3 राज्य बनाने में सफल हुए हैं। कोई सरकार युवाओं की उपेक्षा करके न विकास कर सकती और न ही परिणाम ला सकती है।

सीएम ने कहा कि 2017 के पहले यहां कोई नहीं आता था, लेकिन दुनिया आज यूपी के नौजवानों को मांग रही है। उन्होंने विगत दिनों यूपी में आए जापान के प्रतिनिधिमंडल का भी जिक्र किया। कहा कि 240 सदस्यों का इतना बड़ा दल पहली बार भारत आया। इसमें बड़े नेता, अधिकारी, इडस्ट्री-बिजनेस लीडर्स शामिल थे। वे यूपी के युवाओं को जापान में नौकरी देना चाहते हैं। जर्मनी, इजराइल भी यूपी के नौजवानों को नौकरी देते हैं। इजराइल में यूपी के 5000 नौजवान गए, वहां डेढ़ लाख रुपये प्राप्त करते हैं। घर पर भी पैसा भेज रहे हैं। उनके रहने-खाने की भी व्यवस्था है। इजराइल जब युद्ध लड़ रहा था, तब भी यूपी के युवा वहां काम कर रहे थे।

सीएम ने कहा कि 2017 से पहले किसान खेत में जाने से डरता था। उसकी मोटर चोरी हो जाती थी, लेकिन अब कोई मोटर चोरी नहीं करता, क्योंकि पता है कि ऐसा करने पर अंजाम भुगतना पड़ेगा। 2017 के पहले सरकार के लोग ही मोटर चोरी कराते थे। सीएम ने 2017 के पहले बिजली क्षेत्र की दुर्दशा का भी जिक्र करते हुए बताया कि यूपी के किसानों को सर्वाधिक (10 घंटे) बिजली मिलती है। 16 लाख से अधिक निजी ट्यूबवेल का 3000 करोड़ रुपये का बिजली बिल भी सरकार ने माफ किया। अब इसका भुगतान प्रदेश सरकार करती है। पहली बार यूपी में किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का लाभ मिला है।

जम्मू-कश्मीर के ...

अधिकारियों के मुताबिक, एक खाली पड़े घर से AK-47 राइफल, 3 मैगजीन, 72 कारतूस, 4 हैंड ग्रेनेड और एक IED बरामद किया गया। मामले की जांच जारी है।

मिसाइल तकनीक...

पारंपरिक मिसाइलें लक्ष्य को नष्ट करने के लिए विस्फोटक या गति पर निर्भर करती हैं। वहीं, गैर-पारंपरिक मिसाइलों में परमाणु, जैविक या रासायनिक हथियार लगे होते हैं।

रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यह प्रावधान मिसाइल प्रणालियों के विकास से औद्योगिक उत्पादन तक सफल बदलाव में मदद करेगा।

रक्षा मंत्रालय ने कहा, तकनीक देने का मकसद घरेलू उत्पादन क्षमता बढ़ाना, रक्षा औद्योगिक आधार मजबूत करना और भारतीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) तथा अन्य तकनीकी भागीदारों को सप्लाय चेन में शामिल होने के मौके देना है।

इस पहल से सैन्य क्षमता बढ़ाने, आयात पर निर्भरता घटाने और देश में होने वाले उत्पादन का मूल्य बढ़ाने में मदद मिलेगी। इससे भारत के रक्षा उत्पादन क्षेत्र के विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।

युद्ध और राजनीति ...

पूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने कहा कि पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपने हमलों के नतीजों का सबूत नहीं जुटा सका। उसने चीनी कंपनियों समेत कमर्शियल सैटेलाइट इमेजरी हासिल करने की कोशिश की, लेकिन यह साबित नहीं कर सका कि उसके हमलों से कोई टारगेट हिट हुआ।

जनरल चौहान ने कहा कि सैन्य विकल्पों की संख्या और उनकी गुणवत्ता अचानक तैयार नहीं होती। इसके लिए शांतिकाल में लगातार तैयारी करनी पड़ती है। इसमें कड़ी ट्रेनिंग, युद्धाभ्यास और अलग-अलग संभावित हालात की योजना बनाना शामिल है।

विकल्प इस बात पर भी निर्भर करते हैं कि सैन्य नेतृत्व ने किस तरह की ट्रेनिंग दी है, किस तरह के युद्धाभ्यास किए हैं और किन संभावित हालात पर काम किया है। हर सैन्य विकल्प में किसी न किसी तरह का जोखिम होता है। वह उस राजनीतिक जरूरत को भी पूरा करता है, जिसके लिए उसका इस्तेमाल किया जाना है। ऑपरेशन सिंदूर को करीब 15 महीने हो चुके हैं। जनरल चौहान ने कहा कि इसके बावजूद ऑपरेशन का रणनीतिक असर बना हुआ है और भारत के साथ विदेशों में भी रणनीतिक मामलों के जानकार इस पर नजर रख रहे हैं।

ऐसे ऑपरेशन का आकलन सिर्फ सैन्य कार्रवाई तक सीमित नहीं होना चाहिए। इसमें ऑपरेशन से मिली सीख, सामने आई कमियों को दूर करने के लिए उठाए गए कदम, आधुनिक युद्ध के बदलते तरीके और दुनिया में बनी अनिश्चितताओं को एक साथ देखना जरूरी है।

स्कूल में हिजाब ...

इससे स्कूल के अनुशासन को तय करने का अधिकार संस्थान के बजाय अलग-अलग छात्रों के हाथ में चला जाएगा।

जस्टिस जेजे मुनीर और जस्टिस इंद्रजीत शुक्ला की डिविजन बेंच ने इसके साथ ही नाबालिग छात्रा की याचिका खारिज कर दी। इसमें स्कूल के तय ड्रेस कोड के साथ हिजाब पहनकर कक्षा में बैठने की अनुमति मांगी गई थी।

जस्टिस हेमंत गुप्ता ने कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखा। उनके मुताबिक स्कूल का ड्रेस कोड सभी छात्रों पर समान रूप से लागू होता है और हिजाब को इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक प्रथा साबित नहीं किया गया।

वहीं जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कहा कि इस मामले में यह तय करना जरूरी ही नहीं है कि हिजाब अनिवार्य धार्मिक प्रथा है या नहीं। उनके मुताबिक छात्रा की आस्था और पसंद को अनुच्छेद 19 और 25 के तहत देखा जाना चाहिए।

अनुच्छेद 19: अभिव्यक्ति की आजादी देता है। पहनावे को भी अभिव्यक्ति से जोड़कर अधिकार का दावा किया जा सकता है, लेकिन इस पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।

2027 का चुनाव ...

उन्होंने भाजपा पर लोकतंत्र, संविधान और आरक्षण के लिए खतरा बनने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा पीडीए (पीड़ित, दुखी और अपमानित) वर्ग के लोगों के अधिकार छीन रही है।

अखिलेश यादव ने कहा कि जनता भाजपा की चालबाजी को समझ चुकी है और इस बार उसकी कोई चालाकी नहीं चलेगी। उन्होंने दावा किया कि जनता का भरोसा समाजवादी पार्टी पर है और 2027 में सपा की सरकार बनाने का मन जनता बना चुकी है। उन्होंने कहा कि समाजवादी सरकार बनने पर सभी के साथ न्याय किया जाएगा और प्रत्येक वर्ग को उसका हक व सम्मान मिलेगा। उन्होंने सामाजिक न्याय आधारित व्यवस्था स्थापित करने की बात कही।

नई पीढ़ी को जिम्मेदारी ...

इनके पास सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय है।

अब मेरा काम में दखल कम हो गया: नागपुर के 'एकलव्य एकल विद्यालय शिक्षक-पर्यवेक्षक प्रशिक्षण वर्ग' के कार्यक्रम में 23 अगस्त को गडकरी ने कहा, ' मैं ज्यादा काम नहीं कर पाता। जब कर सकता था, तब किया। अब मेरा काम में दखल कम हो गया है।'

युवाओं से कहा- सुबह उठकर एक्सर-साइज करें: मैं रोज सुबह उठकर ढाई घंटे एक्सरसाइज और प्राणायाम करता हूं। मेरा ट्रेनर मुझसे वर्कआउट करवाता है।

पूर्व वर्ल्ड स्नूकर चैंपियन बच्चों के यौन शोषण में दोषी

आदेश

1993 से 2010 के बीच लड़की और लड़के से दुर्व्यवहार, स्नूकर संस्था ने सदस्यता खत्म की

ग्रेम डॉट ने 2006 में वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता था। वह 2004 और 2010 में भी वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल तक पहुंचे थे।

ग्लासगो, एजेंसी

पूर्व वर्ल्ड स्नूकर चैंपियन ग्रेम डॉट को बच्चों के यौन शोषण के दो मामलों में दोषी पाया गया है। 49 साल के डॉट के खिलाफ ग्लासगो हाई कोर्ट में पांच दिन तक सुनवाई चली। ज्यूरी ने उन्हें 1993 से 1996 के बीच एक लड़की और 2006 से 2010 के बीच एक लड़के के साथ किए गए यौन दुर्व्यवहार से जुड़े दोनों मामलों में दोषी माना।

अदालत ने डॉट की सजा पर फैसला अगली सुनवाई में करने का आदेश दिया है। यह सुनवाई 29 सितंबर 2026 को एडिनबर्ग में होगी। तब तक डॉट हिरासत में रहेंगे। दोषी पाए जाने के बाद वर्ल्ड प्रोफेशनल बिलियर्ड्स एंड स्नूकर एसोसिएशन (WPBSA) ने डॉट की सदस्यता तत्काल प्रभाव से स्थायी रूप से रद्द कर दी। संस्था ने उन्हें खेल से पूरी तरह हटाने का फैसला लिया है और वर्ल्ड स्नूकर से उन्हें हॉल ऑफ फेम से हटाने का अनुरोध भी किया है।

> डॉट ने सुनवाई के दौरान आरोपों को गलत बताया था और कहा था कि उन्होंने कभी किसी के साथ अनुचित व्यवहार नहीं किया। इसके बावजूद ज्यूरी ने दोनों मामलों में उन्हें दोषी माना। पुलिस स्कॉटलैंड के डिटेक्टिव इंस्पेक्टर गैरी स्मिली ने डॉट को 'खतरनाक व्यक्ति' बताया।

दूसरे मामले में करीब 8 साल के लड़के के साथ दुर्व्यवहार

दूसरे मामले में एक लड़के ने अदालत को बताया कि डॉट ने 2006 के बाद उसका यौन शोषण किया। उस समय उसकी उम्र करीब 8 साल थी। उसने अदालत में डॉट पर बाथरूम, कार और अन्य जगहों पर अनुचित तरीके से छूने और यौन दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया। उसने यह भी बताया कि डॉट उसे चिप्स, सॉफ्ट ड्रिंक और एक बार 50 पाउंड देकर 'इनाम' देता था।

डॉट को अप्रैल 2025 में ही प्रोफेशनल स्नूकर की सभी गतिविधियों से निलंबित कर दिया गया था। 2025-26 सीजन खत्म होने के बाद उन्हें प्रोफेशनल रैंकिंग से भी हटा दिया गया था।

खेलों में बच्चों के यौन शोषण के मामले भारत में भी सामने आए हैं। इनमें कई मामलों में कोच या ट्रेनर पर नाबालिग खिलाड़ियों के शोषण के आरोप लगे और कुछ मामलों में अदालत ने दोषी ठहराकर सजा भी सुनाई। 2026 में हरियाणा की फास्ट-ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने राष्ट्रीय स्तर के आर्चरी कोच कुलदीप वेदवान को नाबालिग महिला तीरंदाज से यौन दुर्व्यवहार के मामले में 5 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने POCSO एक्ट के तहत उन्हें दोषी माना और 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।

लड़की ने 1990 के दशक के दुर्व्यवहार के बारे में बताया

सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि डॉट ने 1990 के दशक में एक स्कूली लड़की के साथ कई बार अनुचित व्यवहार किया। अब 40 की उम्र में पहुंच चुकी महिला ने आरोप लगाया कि डॉट ने उसे गलत तरीके से छुआ और उसे यौन गतिविधियों में शामिल करने की कोशिश की। महिला ने अदालत में बताया कि इन घटनाओं से वह डर गई और सदमे में थी। डॉट ने उसे एक टेडी बियर भी दिया था। पुलिस ने 2001 में इन आरोपों को लेकर डॉट से संपर्क किया था, लेकिन उस समय कोई चार्ज नहीं लगाया गया।

ग्रेम डॉट का जन्म 12 मई 1977 को ग्लासगो, स्कॉटलैंड में हुआ था। उन्होंने 2003 में एलेन लैम्बी से शादी की। दोनों के दो बच्चे हैं।

बालाजी और चंद्रशेखर ने कानकुन टेनिस ओपन जीता

फाइनल में मैक्सिको और बेलारूस की जोड़ी को हराया

मैक्सिको, एजेंसी

भारत के एन. श्रीराम बालाजी और अनिरुद्ध चंद्रशेखर ने मैक्सिको में खेले गए कानकुन कंट्री टेनिस ओपन का डबल्स खिताब जीत लिया है। भारतीय जोड़ी ने फाइनल में मैक्सिको के मिगुएल एंजेल रेयेस-वरेला और बेलारूस के इवान ल्युटारेविच को 6-3, 7-6(4) से हराया। इस जीत के साथ बालाजी और अनिरुद्ध को 125-125 एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स रैंकिंग पॉइंट्स और 9,900 डॉलर (करीब 9.5 लाख रुपए) की इनामी राशि मिली।

कानकुन की जीत अनिरुद्ध चंद्रशेखर के लिए चैलेंजर सर्किट का 11वां खिताब है। यह 2026 में उनका दूसरा खिताब भी है।

इस साल इससे पहले अनिरुद्ध ने जापान के ताकेरू युजुकी के साथ बुसान ATP चैलेंजर 125 का खिताब जीता था।

बालाजी के लिए यह जीत और भी खास रही। यह उनका 2026 का पांचवां चैलेंजर खिताब है। इस साल उनके पहले चार चैलेंजर खिताब ऑस्ट्रिया के नील ओबरलाइटनर के साथ आए थे। कानकुन में अनिरुद्ध के साथ खिताब जीतने के बाद बालाजी के चैलेंजर सर्किट पर कुल खिताबों की संख्या 15 हो गई है।

पहले सेट में 6-3 से जीते, दूसरा टाईब्रेकर में

फाइनल के पहले सेट में दोनों जोड़ियों के बीच मुकाबला कड़ा रहा, लेकिन भारतीय जोड़ी ने अहम मौकों पर बढ़त बनाते हुए सेट 6-3 से अपने नाम किया। भारतीय जोड़ी ने पहली सर्विस पर 68% और दूसरी सर्विस पर 81% अंक जीते। दूसरे सेट में भी मुकाबला बराबरी का रहा और सेट टाईब्रेकर तक पहुंचा।

जर्मनी के कीमर को 19-9 से हराया, अब डिफेंडिंग चैंपियन कारुआना से मुकाबला

आर प्रज्ञाननंदा ग्रैंड चेस टूर टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचे

सेंट लुइस, एजेंसी

भारतीय ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञाननंदा ग्रैंड चेस टूर (GCT) 2026 के फाइनल में पहुंच गए हैं। अमेरिका के सेंट लुइस में खेले जा रहे इस टूर्नामेंट में प्रज्ञाननंदा ने सेमीफाइनल में जर्मनी के विंसेंट कीमर को 19-9 से हराया।

प्रज्ञाननंदा ने क्लासिकल और रैपिड गेम के बाद ही फाइनल में जगह पक्की कर ली थी। इसके बाद खेले गए तीन ब्लिट्ज गेम हारने के बावजूद उनके कुल स्कोर पर कोई असर नहीं पड़ा।

अब 25 अगस्त को खिताबी मुकाबले में प्रज्ञाननंदा का सामना डिफेंडिंग चैंपियन अमेरिका के फैबियानो कारुआना से होगा।

ग्रैंड चेस टूर फाइनल की कुल इनामी राशि 4.5 लाख डॉलर है। चैंपियन को 2 लाख डॉलर मिलेंगे। रनर-अप को 1.25 लाख डॉलर और तीसरे स्थान के खिलाड़ी को 75 हजार डॉलर मिलेंगे। टॉप-3 खिलाड़ियों को 2027 ग्रैंड चेस टूर का सीधा आमंत्रण भी मिलेगा।

दूसरे सेमीफाइनल में फैबियानो कारुआना ने अमेरिका के वेस्ले सो को 18-12 से हराया। इसके साथ ही प्रज्ञाननंदा और कारुआना के बीच खिताबी मुकाबला तय हो गया। फाइनल 25 अगस्त को खेला जाएगा। इसमें दोनों खिलाड़ी 0-0 से नई शुरुआत करेंगे। यानी सेमीफाइनल के अंक फाइनल में नहीं जुड़ेंगे। कारुआना इस टूर्नामेंट के डिफेंडिंग चैंपियन हैं और लगातार दूसरी बार खिताब जीतने की कोशिश करेंगे। दूसरी ओर, प्रज्ञाननंदा पहली बार GCT खिताब जीतने के लिए खेलेंगे।

तीन गेम बाकी रहते ही फाइनल पक्का किया

प्रज्ञाननंदा ने सेमीफाइनल के दूसरे क्लासिकल गेम में कीमर को हराकर 9-3 की बढ़त हासिल की। इसके बाद रैपिड गेम्स में भी उन्होंने बढ़त बनाए रखी। रैपिड मुकाबलों के बाद प्रज्ञाननंदा ने 3 गेम बाकी रहते ही सेमीफाइनल अपने नाम कर लिया। यानी ब्लिट्ज के नतीजे उनके फाइनल में पहुंचने की स्थिति को बदल नहीं सकते थे।

इसके बाद चार ब्लिट्ज गेम खेले गए। प्रज्ञाननंदा ने पहले ब्लिट्ज गेम में हार की स्थिति से वापसी करते हुए जीत दर्ज की, लेकिन इसके बाद कीमर ने लगातार तीन ब्लिट्ज गेम जीत लिए। इसके बावजूद सेमीफाइनल का कुल स्कोर 19-9 प्रज्ञाननंदा के पक्ष में रहा।

मनोरंजन

गोविंदा-सुनीता के विवाद के सवाल पर भड़कीं कश्मीरा

नई दिल्ली। गोविंदा और सुनीता आहूजा की शादी को लेकर चल रहे विवाद के बीच कश्मीरा शाह ने कहा कि वो सुनीता आहूजा के साथ हैं।

दरअसल, एक्टर अभिषेक कुमार की बर्थडे पार्टी में पैपराजी से बातचीत के दौरान कश्मीरा से परिवार के विवाद पर प्रतिक्रिया मांगी गई। वहीं, जब कशमीरा ने उनसे गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा के बीच चल रहे पारिवारिक विवाद को लेकर सवाल पूछा था, तो वो पैपराजी पर भड़क गईं। उन्होंने मामले की हर बात पर चर्चा करने से इनकार किया, लेकिन कहा, "मैं इतना जानती हूं कि वह मेरी फैमिली है। मैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करूंगी और अपनी फैमिली की औरतों के साथ खड़ी हूं।" कश्मीरा ने सुनीता के सार्वजनिक तौर पर बोलने के फैसले का भी समर्थन किया। उन्होंने कहा कि अगर सुनीता आज अपनी बात रख रही हैं, तो "कुछ गलत हुआ होगा।" कश्मीरा के ताजा बयान से कुछ समय पहले उन्होंने शादी और बेवफाई को लेकर सोशल मीडिया पर एक क्रिप्टिक पोस्ट शेयर की थी।

सुनीता का सपोर्ट करते हुए बोलीं- वो अपनी बात रख रही हैं तो कुछ गलत हुआ होगा

बैंक रॉबरी पर आधारित है फिल्म इस प्लेटफॉर्म पर हुई ऑनलाइन स्ट्रीम

मनी हाइस्ट की भी बाप निकली ओटीटी की नई फिल्म

नई दिल्ली। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सिनेमा के हर एक जेनर के हिसाब से फिल्मों और वेब सीरीज देखने को मिलती है। जिसमें क्राइम और सस्पेंस थ्रिलर की डिमांड फैंस के बीच काफी देखने को मिलती है। जब बात जुर्म की जाए तो बैंक से पैसे चुराने का क्राइम भी कंटेंट के तौर फिल्ममेकर्स की पहली पसंद रहा है। इसका अंदाजा आप हाल ही में ओटीटी पर स्ट्रीम होने वाली एक नई फिल्म के जरिए आसानी से लगा सकते हैं, जो बैंक रॉबरी के मामले में नेटफ्लिक्स की कल्ट सीरीज मनी हाइस्ट की भी बाप है।

जिस फिल्म के बारे में इस लेख में बात की जा रही है, उसे थिएटर्स के बाद हाल ही में ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर ऑनलाइन स्ट्रीम किया गया है। 2 घंटे 46 मिनट की कहानी वाली इस मूवी में एक ऐसे शख्स की कहानी को दिखाया गया है, जो बैंक कर्मचारी है और उसकी आंखों के सामने लूटेरे उसी के बैंक में लूट को अंजाम देते हैं। इसके बाद वह बैंक कर्मचारी उन लुटेरों से बदला लेता है और बैंक सारा पैसा वापस लाता है। इस दौरान फिल्म की कहानी में काफी रोमांच और थ्रि भी देखने को मिलता है। चलिए अब आपका सस्पेंस खत्म करते हुए बता दें कि यहां बात मलयालम सिनेमा की फिल्म आई नोबडी के बारे में की जा रही है।

> पृथ्वीराज सुकुमारन स्टारर इस मूवी ने अपनी शानदार कहानी के दम पर बड़े पर्दे पर ऑडियंस की दिल जीता था और अब आई नोबडी वही कमाल ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर दिखा रही है और ओटीटी रिलीज के साथ ही मस्ट वॉच बन गई है। अगर आप भी साउथ सिनेमा की फिल्में देखना पसंद करते हैं, तो ये मूवी आपको जरूर पसंद आएगी।

बारिश के मौसम में किशोर कुमार के बेटे ने गाया 'पापा' का कल्ट गाना

47 साल पुराने गीत से जीता जनता का दिल

नई दिल्ली। महान गायक किशोर कुमार (Kishore Kumar) की तरह उनके बेटे अमित कुमार को बेशक उतनी शोहरत नहीं मिल पाई, जिसके वह हकदार हैं। लेकिन फिर भी अपनी मधुर आवाज के दम पर वह अक्सर पुराने गानों को गुनगुनाते हुए नजर आते रहते हैं।

हाल ही में अमित कुमार (Amit Kumar) ने अपने पिता किशोर कुमार का 47 साल पुराना एक कल्ट क्लासिक गीत गाया है, जो बारिश के मौसम के लिए बना था। अब अमित की आवाज में किशोर दा का वह सॉन्ग चर्चा का विषय बन गया है। आइए जानते हैं कि वह गाना कौन सा है। किशोर कुमार ने बतौर सिंगर अपने करियर में कई शानदार गीत गाए। उनमें से अधिकतर गाने राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन के लिए रहे।

बारिश के इस मौसम में अमित कुमार ने अपने पिता का जो पुराना गाना गाया है, वह बिग बी की फिल्म से नाता रखता है। उस गीत के बोल हैं- रिमझिम गिरे सावन... (Rimjhim Gire Sawan)। हाल ही में किशोरिया इंस्टाग्राम पेज पर अमित कुमार ने एक लेटेस्ट वीडियो शेयर किया है। जिसमें वह अपने पापा का लोकप्रिय गीत रिमझिम गिरे सावन... गाना गाते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से वह इस गाने को गा रहे हैं, उसे सुनकर एक पल के लिए आपको किशोर दा की याद आ जाएगी।

तापसी पन्नू की फिल्म पर लगा कहानी चोरी का आरोप?

ओटीटी रिलीज से पहले विवाद में फंसी गांधारी

गांधारी फिल्म को लेकर छिड़ा विवाद
रिलीज से पचड़े में फंसी तापसी की मूवी
इस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आएगी गांधारी

नई दिल्ली। कुछ दिन पहले बी टाउन एक्ट्रेस तापसी पन्नू की अपकमिंग ओटीटी फिल्म गांधारी का एलान हुआ है। अब इस मूवी को लेकर नया विवाद देखने को मिल रहा है। गांधारी के मेकर्स पर कहान चोरी करने का गंभीर आरोप लगा है, जिसके चलते ओटीटी रिलीज से पहली तापसी की फिल्म की मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं।

इंडिया टुडे की रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि गांधारी की राइटर कनिका ढिल्लों ने फिल्म की कहानी चुराई है। दरअसल IIT मद्रास के पूर्व छात्र, मौजूदा समय में सेंट्रल GST और कस्टम्स विभाग में इंस्पेक्टर के पद पर तैनात कल्याण बांदी ने गांधारी की कहानी कॉपी करने का गंभीर आरोप लगाया है। कल्याण एक मशहूर लेखक भी हैं और इंडिया टुडे की रिपोर्ट में उन्होंने ये खुलासा किया है कि साल 2019 में उन्होंने इस मूवी की कहानी लिखी थी और रजिस्टर्ड भी कराई थी। इतना ही नहीं उसी दौरान उन्होंने मोनिका शेरगिल को इस स्टोरी को सुनाया था, जो उस वक्त वूट (Voot) में कार्यरत थीं और आज वह नेटफ्लिक्स की वाइस प्रेसिडेंट हैं। कल्याण बांदी ने बताया है कि सितंबर 2025 में उन्होंने इस मामले को लेकर गांधारी के मेकर्स को नोटिस भी भेजा था। इस मामले को लेकर गांधारी की लेखक कनिका ढिल्लों की टीम की तरफ से कॉपी राइट के आरोपों को सिरे से खारिज किया है और बताया है कि ये कहानी पूरी तरह से उनके द्वारा लिखी गई है।

गांधारी के मेकर्स पर बड़ा आरोप

21 अगस्त ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स (Netflix) इंडिया की तरफ से गांधारी फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर शेयर किया। जिसमें तापसी पन्नू सहित फिल्म की अन्य स्टार कास्ट की झलक देखने को मिली। इसके अलावा मेकर्स ने ये भी स्पष्ट किया कि 3 सितंबर को गांधारी फिल्म को नेटफ्लिक्स पर ऑनलाइन स्ट्रीम किया जाएगा। लेकिन इससे पहले गांधारी की कहानी को लेकर बखेड़ा खड़ा हो गया।

रहमान डकैत नहीं, 'शुक्राचार्य' होगी अक्षय की नई पहचान

महाकाली के बाद भी इन मूवीज में बनेंगे 'असुर गुरु'

- महाकाली से दिखी अक्षय खन्ना की पहली झलक
- असुर गुरु शुक्राचार्य के किरदार में आए नजर
- इन दो मूवीज में भी अक्षय का यही किरदार

नई दिल्ली। धुरंधर फिल्म में खलनायक रहमान डकैत की भूमिका निभाकर अभिनेता अक्षय खन्ना (Akshaye Khanna) ने काफी वाहवाही बटोरी। लेकिन अब लगता है कि महाकाली के गुरु शुक्राचार्य के किरदार के दम पर अक्षय एक नई पहचान बनाने की तैयारी में हैं।

सोमवार को महाकाली (Mahakali) से अक्षय के कैरेक्टर को स्पेशल टीजर वीडियो मेकर्स ने रिलीज किया है, जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। बीते कुछ दिनों में फिल्म छावा में औरंगजेब और फिर फिल्म धुरंधर में रहमान डकैत की भूमिका निभाकर अभिनेता अक्षय खन्ना ने खूब चर्चा बटोरी। उसके बाद बाद फिल्म इंडस्ट्री में भी उनकी मांग बढ़ी दिखी। हालांकि, अक्षय कोई जल्दबाजी न करते हुए प्रोजेक्ट्स का चुनाव काफी सोच-समझकर कर रहे हैं।

आगामी दिनों में वह फिल्म महाकाली में दैत्य गुरु शुक्राचार्य की भूमिका में नजर आएंगे। इस फिल्म की रचना साल 2024 में प्रदर्शित फिल्म तेलुगु फिल्म हनु-मैन के निर्देशक प्रशांत वर्मा ने की है। सोमवार को फिल्म की आधिकारिक प्रदर्शन तिथि के साथ अक्षय अभिनीत शुक्राचार्य के पात्र की झलक के तौर पर पहला टीजर जारी किया गया।

जिसके बाद अक्षय एक बार फिर इंटरनेट मीडिया पर खूब सराहना बटोर रहे हैं। दरअसल, प्रशांत ने बताया था कि उनकी योजना भारतीय पुराणों और ग्रंथों पर आधारित करीब 12 फिल्में बनाने का है।

अमेरिका का ईरान की कमाई के 5 रास्तों पर बैन

इनमें सोना, टेक्नोलॉजी और शिपिंग शामिल, कहा- जो देश बिजनेस करेंगे, उन पर भी कार्रवाई

प्रतिबंध

वाशिंगटन, एजेंसी

अमेरिका ने ईरान की अर्थव्यवस्था के 5 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। जिनका इस्तेमाल ईरान दूसरे देशों में अपनी आर्थिक गतिविधियों के लिए करता है। इनमें डिजिटल एसेट्स (जैसे क्रिप्टोकरेंसी), टेक्नोलॉजी, सोना, एविएशन और शिपिंग सेक्टर शामिल हैं। अमेरिका इन क्षेत्रों के जरिए ईरान की कमाई और अंतरराष्ट्रीय कारोबार को रोकना चाहता है।

यानी अगर कोई देश इन क्षेत्रों में ईरान के साथ ऐसा कारोबार करता है जिससे उसे पैसा या आर्थिक फायदा मिलता है। तो अमेरिका उस देश पर भी प्रतिबंध लगा सकता है या उसे अमेरिकी डॉलर की वित्तीय व्यवस्था से बाहर कर सकता है। अमेरिका ने

अभी यह साफ नहीं किया है कि किन देशों पर सेकेंडरी प्रतिबंध लगाए जाएंगे। हालांकि, चीन, तुर्की और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ईरान के प्रमुख व्यापारिक साझेदार हैं। ईरान के साथ आर्थिक संबंध खत्म करने के अमेरिकी प्रतिबंधों पर भारत पर असर पड़ सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भारत पर सीधे अमेरिकी प्रतिबंध लग जाएंगे। भारत ईरान से कच्चा तेल खरीदता है तो अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण भुगतान और खरीद मुश्किल हो सकती है। ईरान के चाबहार बंदरगाह में भारत की रणनीतिक और कारोबारी रुचि है। अमेरिकी प्रतिबंधों का असर इस परियोजना पर पड़ सकता है।

अमेरिका बोला- अब ईरान के पास सिर्फ दो रास्ते बचे

अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने कहा कि हमने 'ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट' शुरू किया है। यह ईरान और उसके सहयोगी देशों के खिलाफ एक अभियान है। ईरान के सामने अब सिर्फ दो रास्ते हैं। पहला- पूरी तरह से दुनिया से अलग-थलग पड़ना और गुजारे लायक अर्थव्यवस्था। दूसरा- फिर से सामान्य स्थिति की ओर बढ़ना और वैश्विक अर्थव्यवस्था में फिर से शामिल होने का मौका पाना।

सेकेंडरी प्रतिबंध से ईरान के साथ कारोबार करना क्यों मुश्किल?

अमेरिका के सेकेंडरी प्रतिबंधों का असर सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहता। अगर कोई विदेशी कंपनी ईरान के साथ ऐसा कारोबार करती है, जिस पर अमेरिका ने रोक लगा रखी है, तो उस कंपनी पर भी अमेरिकी कार्रवाई हो सकती है।

अमेरिका का सबसे बड़ा दबाव उसकी डॉलर और बैंकिंग व्यवस्था पर है। किसी कंपनी पर प्रतिबंध लगने के बाद उसके लिए अमेरिकी बैंकों और कंपनियों के साथ कारोबार करना मुश्किल हो सकता है। कुछ मामलों में अमेरिकी वित्तीय व्यवस्था तक उसकी पहुंच भी रोकी जा सकती है। यानी किसी भारतीय, चीनी, तुर्की या यूएई की कंपनी के सामने यह खतरा रहता है कि ईरान के साथ कारोबार जारी रखने पर उसे अमेरिकी बाजार और बैंकिंग व्यवस्था में नुकसान उठाना पड़ सकता है।

इसी वजह से कई कंपनियां अमेरिकी प्रतिबंधों में फंसने के जोखिम से बचने के लिए ईरान के साथ कारोबार कम कर देती हैं या उससे दूरी बना लेती हैं।

चीन ने बनाया हवा से हवा में वार करने वाला हाइपरसोनिक व्हीकल

हजारों मील दूर बैठा दुश्मन भी नहीं बचेगा

बीजिंग, एजेंसी

चीनी सेना ने हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल विकसित किए हैं जो हवा से हवा में मार करने वाले हथियार दाग सकते हैं। इसका मकसद हजारों मील दूर मौजूद कमांड-एंड-कंट्रोल एयरक्राफ्ट जैसे अहम लक्ष्यों को निशाना बनाना है।

इस मामले की सीधी जानकारी रखने वाले एक व्यक्ति के अनुसार, यह कामयाबी चीन की उस बड़ी कोशिश का हिस्सा है जिसके तहत वह अपने मिसाइल भंडार का इस्तेमाल लगभग हर तरह के मिलिट्री काम के लिए करना चाहता है। चीन के पास 3,150 से ज्यादा बैलिस्टिक हथियारों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा भंडार है। वहीं दूसरी ओर ईरान के साथ छह महीने की लड़ाई के बाद अमेरिका को एयर डिफेंस मिसाइलों और लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियारों की सप्लाई में मुश्किलों का सामना करना पड़

़हार है।रिपोर्ट में एक व्यक्ति के हवाले से बताया गया कि चीन ने कुछ हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में हवा से हवा में मार करने की क्षमता भी जोड़ी है और कई तरह की मिसाइलों में एंटी-शिप क्षमताएं भी शामिल की हैं।

चीन के साथ संघर्ष के दौरान ऐसे हथियार अमेरिकी हवाई अभियानों के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकते हैं। टैंकर, हवाई चेतावनी और नियंत्रण वाले विमान और यहां तक कि ई-4बी नाइटवॉच जैसे फ्लाइंग कमांड पोस्ट जैसे सपोर्ट एयरक्राफ्ट का मकसद लड़ाई के क्षेत्र से दूर रहकर काम करना होता है।

फास्ट न्यूज

पोर्श की आई कंपनी एमएचपी को खरीदेगी टीसीएस

नई दिल्ली। भारत की सबसे बड़ी IT कंपनी TCS जर्मन कंपनी पोर्श की IT और कंसल्टिंग यूनिट 'MHP' को खरीदेगी। ये डील 320 मिलियन यूरो यानी 3.5 हजार करोड़ रुपए में हुई है।

इस अधिग्रहण के साथ ही दोनों कंपनियों के बीच 1.25 अरब यूरो यानी करीब 14 हजार करोड़ की 5 साल की बड़ी पार्टनरशिप भी हुई है।

बांग्लादेश में चीनी नागरिकों का संगठित अपराधों में हाथ

ढाका। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि पर्यटक बनकर बांग्लादेश आने वाले चीनी नागरिकों का संबंध कई तरह के संगठित अपराधों से पाया गया है, जिनमें अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी, ऑनलाइन धोखाधड़ी और बांग्लादेशी महिलाओं की तस्करी शामिल हैं।

बांग्लादेशी एजेंसियों के हालिया ऑपरेशन्स में ऐसे नेटवर्क का पता चला है, जो देश में स्थानीय लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे थे।

उन्होंने मुख्य रूप से ढाका के उत्तरा, बशुंधरा और निकुंज इलाकों में अपने ठिकाने बनाए हैं।

सेंसेक्स 287 अंक चढ़कर 77,656 पर बंद

नई दिल्ली। शेयर बाजार में आज यानी 25 अगस्त को बढ़त रही। सेंसेक्स 287 अंक की बढ़त के साथ 77,656 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 116 अंक की तेजी रही, ये 24,335 पर बंद हुआ। IT और फार्मा शेयर्स में ज्यादा खरीदारी रही।

अन्नू प्रोजेक्ट्स का IPO आज से ओपन हो गया है। कंपनी इसके जरिए 175.06 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है।

पीपीएफ अकाउंट से बच्चे के लिए बनाएं लाखों का फंड

500 रुपए से खोल सकते हैं खाता

नई दिल्ली, एजेंसी

अगर आप बच्चे के नाम पर निवेश शुरू करने का प्लान बना रहे हैं तो पब्लिक प्रॉविडेंट फंड यानी PPF स्कीम में निवेश कर सकते हैं। इस स्कीम में अभी 7.1% सालाना ब्याज दिया जा रहा है। आप अपने बच्चे के नाम पर PPF अकाउंट खोलकर उसके लिए आसानी से लाखों का फंड तैयार कर सकते हैं। लेकिन इसके कुछ नियम हैं। हम आपको उन नियमों के बारे में बता रहे हैं। बच्चे का PPF अकाउंट केवल माता-पिता या कानूनी अभिभावक यानी लीगल गार्जियन द्वारा ही खोला और चलाया जा सकता है। एक व्यक्ति अपने नाम पर केवल एक ही PPF अकाउंट खुलवा सकता है। हालांकि व्यक्ति अपने PPF अकाउंट के अलावा नाबालिग बच्चे के नाम पर एक अन्य PPF खाता खुलवा सकता है। लेकिन यहां ध्यान

देने वाली बात यह है कि एक पैरेंट्स एक ही बच्चे के नाम पर PPF खाता खोल सकता है। नियमों के मुताबिक, अगर किसी के दो बच्चे हैं तो एक नाबालिग बच्चे का PPF अकाउंट मां और दूसरे का पिता खुलवा सकता है। नाबालिग के PPF अकाउंट के लिए भी एक वित्त वर्ष में कम से कम 500 और अधिकतम 1.5 लाख रुपए जमा कर सकते हैं। लेकिन अगर मां-पिता का खुद का PPF अकाउंट भी है तो उनके खुद के अकाउंट और नाबालिग के PPF अकाउंट दोनों को मिलाकर अधिकतम डिपॉजिट लिमिट 1.5 लाख रुपए सालाना ही रहेगी।

इस्लामाबाद की सरहद यूनिवर्सिटी में पाक आर्मी के अधिकारी की गुंडागर्दी

पत्नी की एक कॉल पर छात्रों पर चलाई गोली

इस्लामाबाद, एजेंसी

पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद की सरहद यूनिवर्सिटी में सोमवार, 24 अगस्त को दिनदहाड़े फायरिंग हुई। प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों पर पाक आर्मी ऑफिसर ने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया। पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर ने छात्रों के प्रोटेस्ट को शांत करने के लिए उनकी डंडे से पिटाई की और यूनिवर्सिटी के अंदर सर्विस गन से फायरिंग की।

सरहद यूनिवर्सिटी के रावत कैंपस में हुई इस घटना के एक चश्मदीद के मुताबिक, स्टूडेंट्स का एक ग्रुप फीस और क्लास शेड्यूल को लेकर अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट के खिलाफ शांति से प्रोटेस्ट कर रहा था। सूत्रों के मुताबिक, स्टूडेंट अफेयर्स की हेड, डॉ. आइना, प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट्स को शांत करने पहुंचीं। जब कुछ स्टूडेंट्स पीछे हटने को तैयार नहीं हुए तो उन्होंने अपने पति, जो एक आर्मी ऑफिसर हैं, उन्हें कैंपस में बुला

लिया। पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर ने कैंपस में आकर छात्रों को डंडे से पीटना शुरू कर दिया। इसके बाद ऑफिसर ने अपनी सर्विस पिस्टल निकाली और हवा में फायर किया। एक स्टूडेंट ने ऑफिसर के खिलाफ एक्शन की मांग करते हुए कहा, 'यूनिफॉर्म पहने उनके पति, जो कि कर्नल या ब्रिगेडियर रैंक के ऑफिसर हैं, वो कैंपस में आए और बिना किसी उकसावे के स्टूडेंट्स को डंडे से मारने लगे। इस बीच, सूत्रों ने बताया कि आर्मी ऑफिसर का पिस्टल लहराते और हवा में गोलियां चलाते हुए वीडियो वायरल होने के बाद, पाकिस्तान आर्मी ने उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन शुरू किया और इंटरनल जांच का ऑर्डर दिया।

'ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट' दुनिया के लिए चेतावनी

वाशिंगटन, एजेंसी

अमेरिका ने ईरान के खिलाफ एक अभूतपूर्व आर्थिक अभियान शुरू किया है, जिसे ट्रेडरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने यह नाम दिया है। इस अभियान में ईरान के फाइनेंशियल नेटवर्क, तेल से होने वाली कमाई और ग्लोबल संबंधों को निशाना बनाने जा रहा है, क्योंकि वाशिंगटन तेहरान पर दबाव बढ़ाना चाहता है। बसेंट ने कहा कि अमेरिकी ट्रेजरी ने राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के निर्देश पर 'ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट' शुरू किया है। उन्होंने कहा कि आज राष्ट्रपति ट्रंप के निर्देश पर, अमेरिकी ट्रेजरी ने 'ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट' शुरू किया है। यह इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान और उसका साथ देने वालों के खिलाफ एक अभूतपूर्व अभियान है। दूसरे विश्व युद्ध में, D-Day हमारे सहयोगियों के साथ मिलकर दुश्मन को उसकी जगहों से हटाने और निशाना बनाने के अभियान

- अमेरिका ने ईरान के खिलाफ 'ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट' शुरू किया।
- ईरान के वित्तीय नेटवर्क और तेल राजस्व को निशाना बनाया जाएगा।
- डिजिटल एसेट्स, टेक्नोलॉजी, सोना, एविएशन, शिपिंग होंगे प्रभावित।

की ऐतिहासिक शुरुआत थी, जिसमें तीसरे देशों में मौजूद ठिकाने भी शामिल थे। आज, उसी भावना के साथ, हम दुनिया भर में ईरान के फाइनेंशियल कनेक्शन के खिलाफ आर्थिक हमला शुरू कर रहे हैं।

नेतन्याहू बोले हमें मिली सिक्योरिटी ऐशोआराम के लिए नहीं, ट्रम्प के बेटे को भी मिल चुकी धमकी

ईरान ने बेटे की हत्या की कोशिश की

तेल अवीव, एजेंसी

इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोमवार को कहा कि ईरान ने उनके परिवार को निशाना बनाया और उनके दो बेटों में से एक की हत्या की कोशिश की थी। उन्होंने यह बात सरकार समर्थक चैनल 14 को फोन पर दिए इंटरव्यू में कही। नेतन्याहू चुनाव से पहले अपने परिवार और दूसरे राजनीतिक नेताओं की सुरक्षा व्यवस्था पर बात कर रहे थे। नेतन्याहू ने कहा, उन्हें दी जा रही सुरक्षा कोई ऐशोआराम नहीं है।

नेतन्याहू के दो बेटे याइर और अवनर हैं। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि उनके दोनों बेटों में से किसे निशाना बनाया गया था। हत्या की कोशिश कब और कैसे की गई।

प्रधानमंत्री के घरों को शीन बेट की सुरक्षा जरूरतों के हिसाब से तैयार किया जाता है। दिसंबर 2022 से नवंबर 2023 के बीच नेतन्याहू के यरुशलम और कैसरिया के निजी घरों की सुरक्षा पर करीब 2.68 करोड़ शेकेल यानी 85.8 करोड़ खर्च हुए। इसमें सिर्फ यरुशलम वाले घर की बालकनी की खिड़कियों की सुरक्षा पर करीब 1.04 करोड़ शेकेल यानी 33.3 करोड़ रुपए खर्च किए गए। 7 अक्टूबर 2023 के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने नेतन्याहू और उनके परिवार के सामान्य निजी अपार्टमेंट में रहने को लेकर भी चिंता जताई थी।

नेतन्याहू के बड़े बेटे याइर पर विवाद

याइर, बेंजामिन नेतन्याहू के बड़े बेटे हैं। वे सरकार या संसद में कोई पद नहीं संभालते, लेकिन सोशल मीडिया पर अपनी राजनीतिक राय और दक्षिणपंथी विचारों के लिए चर्चा में रहते हैं। विवाद तब बढ़ा, जब विदेश में रहने के बावजूद याइर को इजराइली सुरक्षा एजेंसी शिन बेट के सुरक्षाकर्मियों की सुरक्षा मिलती रही। आलोचकों ने सवाल उठाया कि एक वयस्क व्यक्ति के विदेश में रहने पर उसकी सुरक्षा का खर्च इजराइली सरकार क्यों उठा रही है।

> नेतन्याहू की सुरक्षा में इजराइल की आंतरिक सुरक्षा एजेंसी शीन बेट (आईएसए) की बड़ी भूमिका है। सुरक्षा सिर्फ नेतन्याहू तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके सरकारी और निजी घरों की सुरक्षा भी की जाती है।

नेतन्याहू अपने दोनों बेटों याइर और अवनर के साथ।

नेतन्याहू अगला चुनाव हारे, तब भी मिलेगी सुरक्षा

इजराइल में प्रधानमंत्री और उनके परिवार को सुरक्षा मिलती है। लेकिन नेतन्याहू परिवार की सुरक्षा को लेकर विवाद इसलिए बढ़ा, क्योंकि सारा नेतन्याहू और उनके दोनों वयस्क बेटों याइर व अवनर को लंबे समय तक सुरक्षा देने का फैसला हुआ।

तमसा संकेत
tamsa.news@gmail.com

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक, प्रकाशक विद्यादेवी द्वारा कृष्णा डाइनेस्टी प्रिंटिंग प्रेस म० न० 195 सेक्टर 6-बी, वृन्दावन योजना, रायबरेली रोड लखनऊ- 226 029 (उ०प्र०) से मुद्रित कराकर तमसा संकेत भवन शहजादपुर, अकबरपुर जनपद अम्बेडकरनगर (उत्तर प्रदेश) (पिन कोड- 224122) से प्रकाशित

सम्पादक : विद्यादेवी

समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र लखनऊ होगा

समाचार पत्र में प्रकाशित लेख, राजनीतिक विश्लेषण, लेखकों के अपने विचार हैं। सम्पादक का इन विचारों से सहमत होना आवश्यक नहीं हैं।
मो०- 9415799533
R.N.I. NO. 64107/96